मनदीप कौर, मैनेजिंग डायरैक्टर

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

आज तक आमने-सामने

पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

RNI No-Punhin2013/54688 16-30 SEPTEMBER 2025

एस. के. सक्सैना, मुख्य संपादक

साल 2025 /संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com /Help Line 9878552070

इंडिगो की उड़ान को बम की धमकी

मुंबई (एजंसी)–मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई–762 को मंगलवार सुबह बम की धमकी मिलने से दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। उड़ान में करीब 200 यात्री और चालक दल सवार थे। सूचना मिलते ही हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातस्थिति घोषित कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने प्राथमिक जांच के बाद धमकी को अस्पष्ट बताया है। इसके बावजूद यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को देखते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए गए। एयरबस ए321 नियो विमान सुबह 7 बजकर 53 मिनट पर सुरक्षित उतर गया। फ्लाइट राडार 24 वेबसाइट के अनुसार, विमान ने नियत समय पर लैंडिंग की। इस बीच, यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया गया और विमान की पूरी तरह से जांच की गई। घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। इंडिगो की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है।

बाढ़ के मुद्दे पर राजनीति करने से बाज नहीं आईं विपक्षी पार्टियां-मुख्यमंत्री की ओर से कड़ी आलोचना

अवसरवादी नेताओं को पंजाब के लोग कभी नहीं माफ करेंगे, बाढ़ किसी इंसान ने नहीं लाई, यह प्राकृतिक आपदा थी, पंजाब के प्रति उदासीन रवैया अपनाने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, बाढ़ के मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लोग संकट की घड़ी में राज्य के साथ धोखा करने वाले असंवेदनशील और अवसरवादी नेताओं को कभी माफ नहीं करेंगे। आज यहां पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बाढ़ पर बहस को समेटते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाढ़ के संकट के समय एकजुटता दिखाने के बजाय, राज्य के ये तथाकथित अनुभवी नेता सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये नेता केवल

अपने निजी राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो अनुचित है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब राज्य के लोग बाढ़ में राहत और पुनर्वास के लिए दिन–रात प्रयास कर रहे थे, तब ये नेता मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए छटपटा रहे थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्रंप की गाजा शांति योजना का स्वागत

कहा कि यह पहल पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र में स्थायी शांति का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करती है

नई दिल्ली (एजंसी)–प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा संघर्ष समाप्त कराने संबंधी योजना का स्वागत किया है। मोदी ने कहा कि यह पहल फलस्तीनी और इजराइली नागरिकों के साथ–साथ पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को गाजा संघर्ष को खत्म करने की एक व्यापक योजना की घोषणा की। इस मौके पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे।

ट्रंप ने कहा कि इजराइल इस योजना से सहमत है, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि हमास इन शर्तों को स्वीकार करेगा या नहीं। मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'हम गाजा में संघर्ष को समाप्त कराने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। यह फलस्तीनी और इजराइली लोगों के साथ–साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करती है।' प्रधानमंत्री ने यह भी आशा व्यक्त की कि सभी संबंधित पक्ष इस पहल का समर्थन करेंगे और शांति सुनिश्चित करने के प्रयास में एकजुट होंगे।

बगदाद में गुरु नानक देव जी के ऐतिहासिक स्थल के पुनर्निर्माण की मांग

संत सीचेवाल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

नई दिल्ली/चंडीगढ़/ राज्यसभा सदस्य और पर्यावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बगदाद (इराक) में गुरु नानक देव जी के ऐतिहासिक स्थल के पुनर्निर्माण की मांग की है। अपने पत्र में संत सीचेवाल ने लिखा कि उदासियों के दौरान श्री गुरु नानक देव जी सन् 1511 ईस्वी में इराक के शहर बगदाद गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध और अमेरिका–इराक युद्ध के दौरान इस ऐतिहासिक स्थल को भारी नुकसान पहुँचा था। संत सीचेवाल ने कहा कि दुनियाभर में गुरु नानक नाम लेवा संगतें रहती हैं और उनकी श्रद्धा है कि गुरु साहिब का यह पवित्र स्थल फिर से उसी स्वरूप में स्थापित हो। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए इराक के सुप्रीम लीडर सैयद अली हुसैनी खमेनी से संपर्क करें और इस

पवित्र स्थल के पुनर्निर्माण को सुनिश्चित करवाएं। गौरतलब है कि 23 जनवरी 1990 को इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने सिख धर्म के नेताओं से मुलाकात के बाद इस गुरुघर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी थी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संत सीचेवाल ने बताया कि इराक में रहने वाले सिख भाईचारे ने उनसे टेलीफोन पर संपर्क कर यह मांग रखी है कि गुरु नानक देव जी के ढह चुके ऐतिहासिक स्थल का पुनर्निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासियों के दौरान आपसी भाईचारे और शांति का संदेश दिया था, और उसी मार्ग पर चलकर ही पूरी दुनिया में अमन–शांति स्थापित की जा सकती है।

टीवीके जिला सचिव की हुई गिरफ्तारी

करूर (एजंसी)–तमिल अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कझगम ' (टीवीके) की करूर रैली में हुई भीषण भगदड़ के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी के करूर पश्चिम जिला सचिव वी.पी. मथियालगन को गिरफ्तार किया है। इस हादसे में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार, मथियालगन उन तीन पदाधिकारियों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अन्य दो नेताओं में टीवीके के प्रदेश महासचिव बसी आनंद और उप महासचिव निर्मल कुमार का नाम शामिल है। मथियालगन को सोमवार रात करूर–डिंडीगुल सीमा से गिरफ्तार किया गया। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि टीवीके प्रमुख विजय 'जानबूझकर' देर से वेलुसामिपुरम पहुंचे, जिससे रैली स्थल पर भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने न तो भीड़ को नियंत्रित किया और न ही पुलिस की चेतावनियों को गंभीरता से लिया। एफआईआर के मुताबिक, 'कई कार्यकर्ता टिन की छतों और पेड़ों पर चढ़ गए। वहां से नीचे गिरने पर अफरातफरी मच गई और कई लोग दम घुटने से बेहोश हो गए, जिससे असामान्य स्थिति पैदा हुई।'

दक्षिण अमेरिका यात्रा पर राहुल गांधी, नेताओं व व्यापार जगत के लोगों से करेंगे मुलाकात

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह जानकारी दी

नई दिल्ली (एजंसी)–लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के चार देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं जहां उनका प्रमुख नेताओं, छात्रों और व्यापारियों से मुलकात एवं संवाद का कार्यक्रम है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का यह विदेश दौरा कितने दिनों का है। खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, फ्लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुए हैं। उनका चार देशों के नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक जगत के सदस्यों से मिलने का कार्यक्रम है।%% कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ब्राज़ील और कोलंबिया का दौरा करेंगे जहां उनके विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करने की उम्मीद है। पार्टी ने कहा कि वह कई देशों के राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें करेंगे और लोकतांत्रिक एवं रणनीतिक संबंधों को मजबूत

करेंगे। पार्टी ने यह भी कहा कि अमेरिकी शुल्क के मद्देनजर भारत व्यापार और साझेदारी में विविधता लाने के प्रयास कर रहा है और ऐसे में राहुल गांधी व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ मिलकर अवसरों की तलाश करेंगे। वह ब्राज़ील, कोलंबिया और अन्य जगहों के विश्वविद्यालयों के छात्रों से बातचीत करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि यह महत्वपूर्ण यात्रा ऐतिहासिक महत्व रखती है और भारत तथा दक्षिण अमेरिका के बीच गुटनिरपेक्ष आंदोलन, %ग्लोबल साउथ% में एकजुटता तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से लंबे समय से संबंध रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल के अनुसार, राहुल गांधी का यह अभियान इस परंपरा को जारी रखते हुए व्यापार, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच आदान–प्रदान में सहयोग के नए रास्ते खोल रहा है। पार्टी ने यह भी कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को आकार देने और भारत की वैश्विक उपस्थिति को आगे बढ़ाने में भारत के लोकतांत्रिक विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

चंडीगढ़ से आखिरी झुग्गी बस्ती भी हटी

चंडीगढ़ (एजंसी) देश के शहरी विकास की तस्वीर बदलने वाले ऐतिहासिक कदम में चंडीगढ़ ने मंगलवार सुबह अपनी आखिरी झुग्गी बस्ती को भी हटा दिया। सेक्टर–38 वेस्ट की शाहपुर कॉलोनी में करीब पांच सौ झुग्गियां ध्वस्त कर दी गईं, जिससे चंडीगढ़ देश का पहला 'स्लम–फ्री शहर' बन गया। इस कार्रवाई से लगभग दो हजार लोग प्रभावित हुए, जबकि 70 परिवारों को पुनर्वास योजना के तहत नए फ्लैट आवंटित किए गए हैं। सुबह सात बजे यूटी एस्टेट ऑफिस की प्रवर्तन शाखा ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। करीब पांच सौ झुग्गियां हटाई गईं और छह एकड़ सरकारी जमीन खाली कराई गई। आठ टीमें जेसीबी और अन्य मशीनों के साथ लगातार काम करती रहीं। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए 500 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। जमीन खाली होने के बाद प्रशासन ने उसकी घेराबंदी करने का फैसला किया है, ताकि भविष्य में दोबारा कब्जा न हो।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रूस के उप प्रधानमंत्री श्री दिमित्री पात्रुशेव से नई दिल्ली में मुलाकात की

आपसी सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा हुई– श्री चौहान

एस. के. सक्सैना

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रूस के उप प्रधानमंत्री श्री दिमित्री पात्रुशेव से नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में मुलाकात की। इस अवसर पर रूस के उप कृषि मंत्री सहित प्रतिनिधिमंडल भी उपस्थित रहा। इस बैठक में कृषि, विज्ञान, तकनीक, नवाचार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रूस के उप प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम के साथ अत्यन्त सौहार्दपूर्ण एवं सार्थक बैठक हुई। हमने कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने और तकनीकी साझेदारी को और मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। भारत के आलू और अनाज को रूस में प्रवेश मिले उसके लिए चर्चा की गई। श्री चौहान ने कहा कि हमारे मत्स्य क्षेत्र जिसमें निर्यात की काफी संभावनाएं हैं, हमने उस पर भी चर्चा की है। पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात और रूस के बाजार में हमारी पहुंच बने, इस पर भी बातचीत हुई। श्री चौहान ने कहा कि मुझे विश्वास है कि फाइटो–सेनेटरी मानक और नॉन टैरिफ बाधाओं से जुड़े मामलों का शीघ्र ही समाधान होगा। उन्होंने कहा कि हमने शोध और नवाचार पर भी बात की। आईसीएआर और उससे समकक्ष संस्था के

बीच व्यापक सहयोग पर चर्चा जारी है ताकि हम आपस में विज्ञान और तकनीक का आदान–प्रदान कर सकें। इन विषयों पर बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से बातचीत हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत के विद्यार्थियों के रूस में अध्ययन और रूस के विद्यार्थियों के भारत के कृषि संस्थानों में अध्ययन को लेकर भी बातचीत हुई और इस पर सहमति बनी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रूस ने चार भारतीय विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में भी फेलोशिप का लाभ रूस के छात्रों को भी मिलेगा। इससे दोनों देशों के बीच शैक्षणिक–अकादमिक ही नहीं सांस्कृतिक आदान–प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ बीज और कृषि तकनीक आधारित सामाधानों पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अंत में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि रूस के समर्थन और सहयोग से व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों का निश्चित रूप से समाधान निकलेगा तथा इसका लाभ हमारे किसानों उपभोक्ताओं और दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रूस और भारत की मित्रता, शांति और स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना है कि सारी दुनिया ही हमारा परिवार है। इसी भाव से हम अपने राष्ट्र हितों का संरक्षण करते हुए रूस के साथ व्यापार, नवाचार, खाद्य सुरक्षा व शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर रूप से मिलकर काम करेंगे।

उर्वशी रौतेला पहुंचीं ईडी दफ्तर

मुंबई (एजंसी)–अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी रौतेला मंगलवार को '1एक्स बीईटी% नामक एक ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी। उर्वशी रौतेला (31) इस प्लेटफॉर्म की भारत में एंबेसडर है, जो कैरेबियाई द्वीप कुराकाओ में पंजीकृत है। सूत्रों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उसका बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सप्ताह में ईडी ने इस जांच के तहत युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन जैसे क्रिकेटरों के अलावा अभिनेता सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती (पूर्व टीएमसी सांसद) और अंकुश हाजरा (बंगाली सिनेमा कलाकार) से भी पूछताछ की है। कुछ चर्चित सोशल मीडिया हस्तियों से भी पूछताछ की गई है। एजेंसी द्वारा धन शोधन निरोधक कानून के तहत कुछ खिलाड़ियों और अभिनेताओं की करोड़ों रुपये की संपत्ति भी जब्त किये जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि पोर्टल 1

हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब के प्रति केंद्र सरकार की बेरुख़ी पर साधा निशाना

भाखड़ा डैम की अवधि और गाद के बारे में बी.बी.एम.बी. के पास आँकड़े न होने पर उठाए सवाल

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, राज्य के हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ों के कारण पैदा हुयी स्थिति को देखते हुये पंजाब के शिक्षा एवं सूचना और लोक संपर्क मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह समय राजनीतिक बयानबाज़ी का नहीं बल्कि भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने और बाढ़ प्रभावित पंजाब के पुनर्वास हेतु भावी रणनीति तैयार करने का है। उन्होंने बी.बी.एम.बी. के कामकाज और इस प्राकृतिक आपदा पर विपक्ष द्वारा की जा रही बेबुनियाद ब्यानबाजी करके की जा रही राजनीति पर भी गंभीर सवाल उठाए। आज पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए श्री बैंस ने विपक्ष से अपील की कि वे संकुचित राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर लोगों की भलाई को प्राथमिकता दें। उन्होंने बाढ़ों के भीषण प्रभावों पर प्रकाश डाला, जिनमें 59 लोगों की मौत, घरों का विनाश, हज़ारों पशुओं की क्षति और राज्य के कृषि क्षेत्र को गहरा आघात पहुँचना

शामिल है। उन्होंने कहा कि असल नुकसान इससे भी व्यापक है क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में साँप काटने, संपर्क टूटने के कारण अलग–थलग पड़ जाने जैसी वजहों से भी कई जानें गईं। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को गंभीर क्षति पहुँची है, जिनमें 3,200 से अधिक स्कूल प्रभावित हुए और 1,300 से अधिक कक्षाएँ उपयोग योग्य नहीं रहीं। उन्होंने कहा, फ्पाँच लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। इन फसलों पर निर्भर पंजाब की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। पंजाब की वे महिलाएँ जो किसी को गंदी जूती पहनकर घरों में नहीं घुसने देती थीं, उनके आँगन अब कीचड़ और गाद से भरे पड़े हैं। श्री बैंस ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) पर निशाना साधते हुए बोर्ड के चेयरमैन द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए भ्रामक बयान का ज़िक्र किया। उन्होंने केंद्रीय जल आयोग की 24 अप्रैल की रिपोर्ट से तकनीकी आँकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें उल्लेख था कि पंजाब के प्रमुख जलाशयों में 44.85 प्रतिशत पानी, जो सामान्य से काफी कम था, और हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में 40.60 प्रतिशत पानी संचित था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भाखड़ा डैम में पानी का स्तर 1555 फ़ीट था, पानी की गंभीर कमी के बावजूद बी.बी.एम.बी. ने पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा की ओर मोड़ने की कोशिश की, जिससे पावर हाउस बंद होने का ख़तरा पैदा हो गया।

संपादकीय

गूंगा वह नहीं जो बोलता नहीं! गूंगा वह हो जो सच्च नहीं बोलता!! मैं कि झूठ बोलिया ?

आवारा मवेशियों का सड़कों झुंडों में घूमना – दुर्घटनाओं का मुख्य कारण

आवारा जानवरों के कारण आये दिन – लोगों की जा रही हैं – जानें

आखिर जिम्मेदार कौन ? जरा सोचिए

आजकल सड़कों पर आवारा जानवर (मुख्यतः मवेशी) यातायात के लिए एक बड़ा खतरा है। आये दिन सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं। लोगों की कीमती जाने जा रही हैं।साथ ही पशुधन की भी

हानि हो रही है। ये न केवल राहगीरों, आम नागरिकों बूढो एवं बच्चो के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, बल्कि सड़क यातायात को बाधित भी करते हैं एवं बारिश के दौरान यह समस्या और भी बढ़ जाती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आवारा पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना और उन्हें देखभाल प्रदान करना आवश्यक है। जानलेवा दुर्घटनाएँ – आवारा मवेशी अचानक सड़क पर आ जाते हैं, जिससे वाहन चालक संतुलन खो देते हैं और दुर्घटनाएँ होती हैं। मानव जीवन की हानि- मवेशियों के कारण हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत हो जाती है और वे घायल भी हो जाते हैं। यातायात में बाधा– सड़कों पर मवेशियों का झुंड यातायात को धीमा कर देता है या पूरी तरह रोक देता है। पशुधन की हानि– दुर्घटनाओं में पशु भी घायल होते हैं या मारे जाते हैं। समस्या का समाधान – आवारा पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना- पशुओं को सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर रखना चाहिए जहाँ उन्हें भोजन, पानी और आवास मिल सके।जागरूकता अभियान– लोगों को आवारा पशुओं को न छेड़ने और उनका सम्मान करने के बारे में शिक्षित करना चाहिए। संस्थाओं का सहयोग– धार्मिक, समाजिक संगठनों एवं दानी सज्जनों के द्वारा आवारा पशुओं को भोजन, पानी, आवास और इलाज प्रदान करके अधिक से अधिक सहयोग देना चाहिए। नगर निगम/प्रशासनिक कार्रवाई- स्थानीय प्रशासन को सड़कों पर से आवारा पशुओं को हटाने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। नियमित पशुधन सर्वेक्षण– आवारा पशुओं की संख्या का पता लगाने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए नियमित सर्वेक्षण आवश्यक हैं। बुद्धिजीवी वर्ग के अनुभव के अनुसार सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को कांजी हाऊस या गोशालाओं में संभालना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा जो काऊ टैक्स जनता से वसूला जा रहा है उसका उचित उपयोग करके पशुधन को संभालने से काफी हद तक दुर्घटनाओं से निजात पा सकते है एवं कीमती जानें बच सकती हैं। इस समस्या के बारे आप भी सोचें, कि जिम्मेदार कौन?

आज तक आमने सामने
RNI NO -PUNHIN0/2013/54688
Printed by Mandeep Kaur, Published by Mandeep Kaur, Owned by Mandeep Kaur & Printed at Dashmash Printers 178-179 Ranjit Nagar, Jalnadhar City, Published 87 Ranjit Nagar Near Bus Stand, Jalandhar, Punjab
Editor Surinder Kumar (SK Saxena)
Responsible for selection of News under the PRB ACT.
All Rights Reserved Reproduction in whole or in Part without Permission in Prohibited, All disputes shall be settled at Jalandhar Jurisdiction only
Faxt No. : 0181-5024001, Conact No : 0181-5077100

आवश्यक सूचना

आज तक आमने-सामने का इस समाचार पत्र में मुद्रित विज्ञापनों (डिस्प्ले/क्लासीफाईड) के तथ्यों सबंधी कोई दायित्व नहीं है। महारा समाचार पत्र इनको सत्यापित नहीं करता। पाठकों से अनुरोध है कि वे इन विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पूर्व सभी तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर लें। -प्रधान संपादक

टी.सी. इंटरनेशनल स्कूल ने वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर एक विशेष आयोजन किया

एस. के. सक्सैना

जालंधर, टी.सी. इंटरनेशनल स्कूल ने वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर एक विशेष आयोजन किया, जिसमें छात्रों को जालंधर के वंडरलैंड अम्यूज़मेंट और वॉटरपार्क की यात्रा पर ले जाया गया। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन श्री रविंदर शर्मा ने छात्रों को पर्यटन के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। श्री रविंदर शर्मा ने कहा कि पर्यटन न केवल हमें नई जगहों और संस्कृतियों से परिचित कराता है, बल्कि यह हमारे देश की आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन से हमें विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने का अवसर मिलता है, और यह हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने और समझने में मदद करता है। छात्रों ने वॉटरपार्क में मज़े किए और विभिन्न राइड्स का आनंद लिया। उन्होंने नई जगहों का अन्वेषण किया और अपने दोस्तों के साथ मज़े किए। यह यात्रा छात्रों के लिए एक यादगार अनुभव था, जिसने उन्हें पर्यटन के महत्व के बारे में जानने का अवसर प्रदान किया। टी.सी. इंटरनेशनल स्कूल का यह प्रयास छात्रों को पर्यटन के महत्व से अवगत कराने और उन्हें नई चीजों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करने के लिए एक सराहनीय कदम है। स्कूल का उद्देश्य छात्रों को न केवल शिक्षा प्रदान करना है, बल्कि उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं से भी परिचित कराना है।

श्री तरुण चुग जी द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हरमेल सिंह टौहड़ा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि

मनदीप कौर

चंडीगढ़, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुग जी ने आज पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हरमेल सिंह टौहड़ा जी की आत्मा की शांति के लिए आयोजित अंतिम अरदास समारोह में शामिल होकर उन्हें नमन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का शोक संदेश पढ़ा। इस अवसर पर श्री तरुण चुग जी ने श्री टौहड़ा जी के परिजनों से मिलकर दुख साझा किया और उनके साथ बिताए अनमोल पलों को याद करते हुए भावनात्मक स्मृतियाँ साझा कीं। श्री तरुण चुग जी ने प्रार्थना की कि अकाल पुरख दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ईश्वर की रज़ा मानने की शक्ति प्रदान करें।

प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और जे.पी. नड्डा का शोक संदेश लेकर पहुँचे

डी.जी.पी. द्वारा जालंधर में इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के पहले चरण की शुरुआत

42 करोड़ की लागत वाला प्रोजेक्ट ट्रैफिक को सुचारू बनाने के साथ–साथ सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगा- डी.जी.पी. गौरव यादव

पंकज

जालंधर, पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) गौरव यादव ने सोमवार को जालंधर में इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आई.टी.एम.एस.) के पहले चरण का शुभारंभ किया, जो शहर के ट्रैफिक रेग्युलेशन और निगरानी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डी.जी.पी. ने कहा कि एस.ए.एस. नगर के बाद जालंधर इस अत्याधुनिक प्रणाली को लागू करने वाला पंजाब का दूसरा शहर बन गया है। इस अवसर पर उनके साथ पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर, डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल और नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि भी मौजूद थे। 42 करोड़ रुपये की लागत से विकसित सिटी सर्विलांस और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का पहला चरण पुलिस लाइन में स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आई.सी.सी.सी.) से जोड़ा गया है। इसमें 13 महत्वपूर्ण जंक्शनों पर स्थापित 142 हाई–रेजोल्यूशन कैमरों को एकीकृत किया गया है। इस सिस्टम में 102 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ए.एन.पी.आर.) कैमरे, 40 रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन (आर.एल.वी.डी.) कैमरे, 83 बुलेट कैमरे, चार पी.टी.जेड कैमरे, 30 विजुअल मैसेज डिस्प्ले स्क्रीन और दो स्पीड वायलेशन डिटेक्शन साइटों पर 16 कैमरे शामिल हैं। शहरी व्यापी निगरानी योजना के तहत 1003 कैमरों के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम और इमरजेंसी कॉल बॉक्स प्रणाली स्थापित करने की योजना है। इसकी प्रमुख विशेषता ई–चालान प्रणाली है, जो एन.आई.सी. के 'वाहन' और 'सारथी' डेटाबेस के साथ एकीकृत है और लाल बत्ती उल्लंघन, ओवरस्पीडिंग और गलत दिशा में ड्राइविंग पर स्वचालित चालान जारी करने में सक्षम है। पंजाब सरकार की कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए डी.जी.पी. ने कहा कि सितंबर 2024 से अब तक पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित तत्वों द्वारा राज्य में शांति भंग करने की 26 से अधिक कोशिशों को नाकाम किया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 57 अतिरिक्त कंपनियां प्राप्त हुई हैं। पंजाब सरकार के 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस ने लगभग 20,000 एफ.आई.आर. दर्ज की हैं, 31,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और रिकॉर्ड 87 प्रतिशत सजा दर हासिल की है, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस शांति और सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने के साथ–साथ राज्य से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदेश में बागवानी के विकास के लिए हर कदम उठाया जाएगा-मोहिंदर भगत

रमन कुमार

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के मालिकों और किसानों के साथ पंजाब भवन, चंडीगढ़ में एक विशेष बैठक की गई। इस बैठक के दौरान कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के मालिकों और किसानों ने बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत को अपनी समस्याओं के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया। मंत्री ने उनकी समस्याओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उनकी जायज़ मांगों को जल्द हल करने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के मालिकों ने सरकार की ओर से मिल रहे वित्तीय लाभ के लिए पंजाब सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद किया। इस मौके पर बागवानी मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सरकार द्वारा नए बाग लगाने, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, तकनीकी सहायता और मार्केटिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इससे किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उत्पादकता और आय में लगातार वृद्धि की जा रही है। मंत्री श्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों और बागवानी क्षेत्र से जुड़े हर वर्ग की भलाई के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बागवानी के विकास के लिए हर कदम उठाया जाएगा, ताकि किसानों की आय बढ़े और नए रोज़गार के अवसर पैदा हों। बैठक के दौरान पंजाब के विभिन्न जिलों से कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के मालिकों और विभिन्न किसानों के अलावा बागवानी सचिव श्री बसंत गर्ग, निदेशक श्रीमती शैलिंदर कौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

बागवानी मंत्री द्वारा कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के मालिकों और किसानों के साथ विशेष बैठक

बाढ़ पीड़ित किसानों के खेत समतल करने के लिए रोज़ चल रहे हैं 8 घंटे ट्रैक्टर

50 दिनों से संत सीचेवाल लगातार कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों की मदद, बाढ़ पीड़ितों के लिए किसी सांसद का रोज़ाना इतना समय देना अपने आप में एक मिसाल

कैप्टन सुभाष चंद्र

सुल्तानपुर लोधी, बाऊपुर मंड क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल को आज 50 दिन पूरे हो गए हैं। बाऊपुर मंड क्षेत्र में किसानों द्वारा ब्यास दरया का पानी रोकने के लिए बनाया गया 32 किलोमीटर का घेरा 8 जगहों से टूट गया था। बांधों में अलग–अलग दरारों के कारण हुई तबाही का सही आकलन अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन संत सीचेवाल पहले दिन यानी 11 अगस्त से ही बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल रोज़ाना सुबह साढ़े 7 बजे से लेकर देर शाम साढ़े 7 बजे तक लगभग 12 घंटे अपनी सेवाएँ बाढ़ पीड़ितों को दे रहे हैं। वे हर रोज़ सुल्तानपुर लोधी से सीधा बाऊपुर मंड क्षेत्र पहुँचते हैं। पंजाब और अन्य राज्यों से खेत समतल करने आए ट्रैक्टरों की ड्यूटी बाँटते हैं और खुद भी कमर कसकर ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं। बाऊपुर मंड के गाँव भैणी कादर बख्श के चार किसानों की ज़मीन में बने 35 से 40 फुट गहरे टुए को भरने में संत सीचेवाल खुद लगे हुए हैं। जागता पंजाब के प्रधान राकेश शांति दूत ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए देश के किसी सांसद द्वारा रोज़ाना इतना समय देना अपने आप में एक बेमिसाल उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर देश के सभी राजनीतिक नेता संत सीचेवाल की तरह काम करने लगें तो लोग राजनीति को गंदगी भरी सियासत कहना बंद कर देंगे। आज करीब 100 ट्रैक्टर उस टुए को भरने में लगे हुए हैं। यह गड्ढा इतना गहरा है कि पिछले 7 दिनों से रोज़ाना 100 ट्रैक्टर इसमें मिट्टी डाल रहे हैं। संत सीचेवाल ने 11 अगस्त से अब तक बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ही सारा समय समर्पित किया हुआ है। उन्होंने इसके लिए अपना विदेश दौरा भी रद्द कर दिया था। भैणी कादर बख्श के बांध तक पहुँचने के लिए पहले ट्रैक्टर को पानी के भीतर ले जाना पड़ता था। इस काम के लिए वैकल्पिक

रास्ता बनाया गया, जिससे ट्रैक्टरों की बांध तक पहुँच आसान हो गई।

बाऊपुर मंड क्षेत्र के लिए मसीहा बने संत सीचेवाल

जिन किसानों की ज़मीन में यह गड्ढा भरा जा रहा है, उन्होंने कहा कि संत सीचेवाल उनके लिए मसीहा बनकर आए हैं। इतना गहरा और चौड़ा गड्ढा कौन भर सकता था। उनके 20 खेतों से भी रेत हटाई जा रही है। सांगरा गाँव के सरपंच कमरजीत सिंह ने बताया कि 30 दिनों तक संत सीचेवाल नाव द्वारा प्रसाद लाकर वितरित करते रहे। इतने गहरे पानी में जब कोई भी डेरे से बाहर निकलने में सक्षम नहीं था, तो उस मुश्किल घड़ी में सबसे पहले सुबह का खाना हर घर तक पहुँचाया जाता था। गाँव बाऊपुर के निवासी सतिंदर सिंह बग्गा ने बताया कि बाढ़ के दौरान संत सीचेवाल पहले दिन से ही इस इलाके के लिए मसीहा बनकर आए, जिन्होंने इंसानों से लेकर घरों में पाले गए पालतू कुत्तों और पशुओं के खाने–चारे तक की व्यवस्था की।

मनदीप कौर, मैनेजिंग डायरैक्टर

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

आज तक आमने-सामने

हरियाणा ख़बरनामा

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

16-30 SEPTEMBER 2025

एस. के. सक्सैना, मुख्य संपादक

साल 2025 /संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com /Help Line 9878552070

प्रधानमंत्री जब भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हरियाणा का नाम अवश्य लेते हैं- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

प्रदेश में स्थापित एमएसएमई उद्योगों ने 15 लाख युवाओं को दिया रोजगार

पंकज

चंडीगढ़, – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हरियाणा का नाम अवश्य लेते हैं। हरियाणा प्रदेश ने प्रत्येक अभियान में शुरू से ही मजबूती के साथ भूमिका अदा की है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार लगातार एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में करीब 15 लाख युवाओं को एमएसएमई के माध्यम से रोजगार मिला है। इसी बदौलत एमएसएमई का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हरियाणा को मिला है। मुख्यमंत्री सोमवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत

विधानसभा लाडवा के मंडल बाबैन में आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान से देश की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे नंबर पर पहुंची है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। इन योजनाओं को अपनाते हुए देश आत्मनिर्भर के साथ–साथ स्वावलंबी बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का विजन रखा है। इस विजन को पूरा करने के लिए पहले आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशालाओं का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को एक साथ जोड़ने का है। उन्होंने आह्वान किया कि कार्यकर्ता सरकार की नीति, नियम, योजना और अभियानों को जन–जन तक पहुंचाने का काम करें ताकि आमजन सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके।

नागरिकों को सामाजिक कार्यों में अपनी जनभागीदारी निभानी चाहिए-केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल

करनाल स्थित श्रीकृष्ण गौशाला में आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल

मनदीप कौर

चण्डीगढ़, – केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि करनाल के लोगों में भरपूर सेवा भावना है। नागरिकों को सामाजिक कार्यों में अपनी जनभागीदारी निभानी चाहिए। वे खुद भी पिछले 11 साल से करनाल की सेवा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रविवार को करनाल श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अवसर होते हैं जब हम प्रेरणा की बातें सोचते हैं। रामलीला के माध्यम से राम के जीवन के आदर्शों को अपनाने और रावण रूपी बुराई को त्यागने की प्रेरणा मिलती है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस भी आता है। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन ईमानदारी और सदाचार की मिसाल रहा है। इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, पौधारोपण, खेल प्रतियोगिताएं, गौ सेवा आदि के कार्य जारी हैं।

सिख समाज एक बहादुर कौम, धर्म की रक्षा के लिए सिर कटा दिये, लेकिन झुके नहीं - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

एस. के. सक्सैना

1984 सिख दंगों के पीड़ित परिवारों की पीड़ा हमारी पीड़ा, सिख समाज का संघर्ष हम सब के लिए प्रेरणादायक

चण्डीगढ़, – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिख समाज एक बहादुर कौम है, जिसने धर्म की रक्षा के लिए सिर कटा दिये, लेकिन झुके नहीं। 1984 सिख दंगों में पीडित परिवारों की पीड़ा हमारी पीड़ा है और सिख समाज का संघर्ष हम सब के लिए प्रेरणादायी है व उनका आत्म–सम्मान सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज यहां प्रदेश भर से आए सिख समाज के लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। प्रदेश सरकार द्वारा मानसून सत्र के दौरान 1984 के दंगा पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव पारित करने पर सिख समाज ने आज मुख्यमंत्री का सम्मान एवं आभार व्यक्त किया। ऐसे 121 परिवारों के एक–एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया था, जिनके किसी सदस्य की जान दंगों में चली गई थी। उन्होंने कहा कि सिख समाज की कुर्बानियों तथा वीरता पर सभी भारतवासियों को भी गर्व है। गुरुओं के आदर्शों व सिद्धान्तों पर चलते हुए जहां स्वतंत्रता आन्दोलन में बढ़चढ़ कर भाग लिया, वहीं आजादी के बाद भारत माता की रक्षा के लिए बड़ी–बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 1984 के काले दिन भारतीय लोकतंत्र और मानवता के इतिहास में एक कलंक के रूप में अंकित श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिखों की सेवा भावना भी विश्व विख्यात है। जहां भी मानवता पर संकट आता है, वहां पर उनकी रक्षा और सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस समाज ने देश व धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी उसी समाज को वर्ष 1984 में निर्दयता से जख्मी किया गया। 1984 के वे काले दिन भारतीय लोकतंत्र और मानवता के इतिहास में एक कलंक के रूप में अंकित हैं। निर्दोष सिख समाज के हजारों लोगों ने उस हिंसा में अपने प्रियजनों को खो दिया और अपने घर–बार से उजड़ गए।

1984 दंगों के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उठाए ठोस कदम, सम्मान देने का भी किया काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सत्ता में आने के बाद यह संकल्प लिया कि वर्ष 1984 की त्रासदी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ साथ उन्हें सम्मान भी दिया जाएगा। हमने विशेष जांच आयोग गठित किए, दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया को तेज किया और मुआवजा योजनाओं को लागू किया। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी परिवार को न्याय से वंचित न रहना पड़े। प्रदेश में किसी भी नागरिक के साथ, उसकी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर अन्याय नहीं होगा।

टेक्नोलॉजी के ज्ञान ने जलाई गोधन के प्यार की "पंचलाइट"

हास्य नाटक पंचलाइट देख दर्शक हुए लोटपोट, कुरुक्षेत्र के कलाकारों ने बटोरी वाहवाही

कुरुक्षेत्र, संजीव कुमारी–ससुरी पंचलाइट के चक्कर में हम तो सुबह से चुल्हा– चौका भी ना किए, यही सोचे थे कि पंचलाइट आएगा तो गुजिया बनाकर पूरे टोला को खिलाएंगे, पर अब ना ई पंचलाईट जलेगा ना ही गुजिया बनेगी। इसी तरह के संवादों के साथ न्यू उत्थान थियेटर ग्रुप के कलाकारों ने कला कीर्ति भवन में हंसी के फव्वारे छोड़ते हुए विकास शर्मा द्वारा निर्देशित नाटक पंचलाइट प्रस्तुत कर अशिक्षा पर प्रहार किया। मौका था न्यू उत्थान थियेटर ग्रुप की 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उत्थान उत्सव के दूसरे दिन का। हरियाणा कला परिषद और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला के संयुक्त सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय नाट्य उत्सव में दूसरे दिन हरियाणा पशुधन बोर्ड के अध्यक्ष धर्मबीर मिर्जापुर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्यकार एवं समाजसेवी डॉ. जयभगवान सिंगला ने की। विशिष्ट अतिथि के रुप में हरियाणा कला परिषद के पूर्व निदेशक संजय भसीन तथा उपपुलिस अधिक्षक रोहताश जांगड़ा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मंच का संचालन डा. मोहित गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम से पूर्व न्यू उत्थान थियेटर ग्रुप के अध्यक्ष नीरज सेठी, सदस्य नरेश सागवाल तथा धर्मपाल गुगलानी

ने अतिथियों को तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत किया। मुनरी से ब्याह की शर्त पर गोधन ने जलाई पंचलाइट, विकास शर्मा के निर्देशन में फणीश्वरनाथ रेणु की बहुचर्चित कहानी पंचलाइट बिहार के गांव के भोले–भाले लोगों के इर्द–गिर्द घूमती है। जहां गांव में बिजली न होने के कारण महतो टोली के लोग दण्ड और जुर्माने के पैसे इकट्ठे करके पंचलाइट खरीद लेते हैं। जब शहर से पंचलाइट गांव में आती है तो खूब खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि गांव के किसी भी व्यक्ति को पंचलाइट जलानी नहीं आती। टोला वाले पंचलाइट न जलाने के लिए एक दूसरे को कहते हैं, किंतु कोई भी पंचलाइट जलाने में सफल नहीं हो पाता। लेकिन गांव का एक आवारा लड़का गोधन जो पढ़ा लिखा है तथा जिसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, उसे ही पंचलाइट जलानी आती है। गोधन गांव की ही लड़की मुनरी से प्यार करता था। लेकिन मुनरी से प्यार करने वाले कल्लू को उन दोनों का मिलना पसंद नहीं था और वह मुनरी की अम्मा को सब बता देता है। मुनरी की अम्मा पंचायत बुला लेती है, जिसमें फैसला होता है कि गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। इस प्रकार गोधन और मुनरी का मिलना जुलना बंद हो जाता है और गोधन को गांव से निकाल दिया जाता है। लेकिन पंचलाइट आने पर मुनरी सबको बताती है कि गोधन को ही पंचलाइट जलानी आती है। इज्जत बचाने के चक्कर में सरपंच गोधन को बुलाकर पंचलाइट जलाने के लिए कहता है, लेकिन गोधन शर्त रखता है कि यदि मुनरी से उसकी शादी करवाई जाए, तभी वह पंचलाइट जलाएगा। पंचायत उसकी बात मान लेती है और गोधन का मुनरी से ब्याह करवाने का वादा करती है। तब गोधन पंचलाइट जला देता है और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इस प्रकार हंसी के फव्वारे छोड़ते नाटक का खुशी–खुशी समापन होता है। नाटक में राजीव कुमार, मनू महक माल्यान, निकेता शर्मा, शिवकुमार किरमच, चंचल शर्मा, रचना अरोड़ा, विकास शर्मा, गौरव दीपक जांगड़ा, राजकुमारी, सुनैना, पार्थ शर्मा, साहिल खान, सागर शर्मा, निखिल पारचा, आकाशदीप, प्रियांशु बंसल, गोविंदा व चमन व विशाल ने सहयोग दिया। नाटक के उपरांत मुख्य अतिथि धर्मबीर मिर्जापुर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को आईना दिखाने का सबसे उत्तम ढंग नाटक है। नाटक के माध्यम से कलाकार प्रत्येक बात को लोगों तक आसानी से पहुंचाते हैं। पंचलाइट में शिक्षा को महत्व दिया गया है। जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरुरी है। नाटक मंचन के दौरान हरजीत सिंह, गोल्डी सिंगला, अर्पित भसीन, अनु माल्यान, किरण गर्ग, अन्नपूर्णा शर्मा, कपिल बत्रा सहित भारी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे।

धान की खरीद 22 सितंबर से हुई शुरू लेकिन सरकार के अधूरे इंतजाम से रोष में है किसान संघ

लाडवा विनोद कुमार यादव – भारतीय किसान संघ के कुरुक्षेत्र जिले अध्यक्ष दीपक विशाल शर्मा ने बताया की धान की खरीद 22 सितंबर से शुरू हो चुकी लेकिन सरकार के अधूरे इंतजाम के कारण किसानों की दुर्गति हो रही है। जिसको लेकर भारतीय किसान संघ सरकार को जगाना चाहता है या तो खरीद व धान का उठान सही तरीके से करें वरना भारतीय किसान संघ सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा वही संभाग संगठन मंत्री विजय गौड ने कहा भारतीय किसान संघ धान व बाजरे की खरीद में सरकार का उदासीन रवैया देखते हुए चिंतित है जो सरकार अपने आप को किसान हितेषी बताती है लेकिन इस सरकार से किसान वर्ग दुखी है सरकार को चाहिए किसानों का ध्यान रखते हुए खरीद में पारदर्शिता बरती जाए वहीं प्रदेश महामंत्री रामवीर सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय किसान संघ के सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं, कि वह अनाज मंडियों की खरीद तोल की जांच करें सरकार अपने वादे से मुकर रही है सभी मंडियों में डिजिटल कांटे लगाने का वादा किया था। तोल उसी पर होगा लेकिन एक भी मंडी में कंप्यूटराइज कांटा दुकानदार के पास नहीं है। इसको लेकर भारतीय किसान संघ पूरे हरियाणा में अनाज मंडी में जाकर विरोध दर्ज कराएगी। इस मौके पर कुरुक्षेत्र भारतीय किसान संघ की कार्यकारिणी उपस्थिति रही।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित विधायी प्रशिक्षण कार्यशाला का किया उद्घाटन

पंकज

स्पष्ट और पारदर्शी कानून ही लोकतंत्र की आत्मा – ओम बिरला, विधायी ड्राफ्टिंग में प्रशिक्षण से नए कानून बनेंगे जनकल्याणकारी और समयानुकूल

चंडीगढ़, – लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि विधायी ड्राफ्टिंग लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। स्पष्ट, सरल और पारदर्शी कानून ही लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं और जनता का विश्वास शासन–प्रशासन में और अधिक मजबूत करते हैं। समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कानूनों में संशोधन और नए कानूनों का निर्माण आवश्यक है। हमारा प्रयास है कि हम बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करके आने वाले समय में ऐसे विधायी मसौदे तैयार कर सकें, जो नागरिकों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए अधिक प्रभावी साबित हों। लोकसभा अध्यक्ष आज हरियाणा विधानसभा द्वारा लोकसभा की संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के सहयोग से चंडीगढ़ सेक्टर–26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में विधायी प्रारूपण एवं क्षमता संवर्धन विषय पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन करने उपरांत संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष श्री यू टी खादर फरीद, हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण लाल मिड्ढा उपस्थित रहे। श्री ओम बिरला ने कहा कि हरियाणा की धरती लोकतांत्रिक मूल्यों की सदैव प्रहरी रही है। इस राज्य ने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर देशभर में अपनी विशेष पहचान बनाई है।

पिहोवा के गोविंदानंद आश्रम में मासिक कन्या पूजन भंडारा आयोजित

जरूरतमंद कन्याओं की समय समय पर हर संभव सहायता करता है आश्रम

पिहोवा, वैद्य प्रमोद कौशिक - पिहोवा के श्री गोविंदानंद ठाकुर द्वारा आश्रम में आज महामंडलेश्वर 1008 स्वामी विद्यागिरि जी महाराज, श्रीमहंत बंशी पुरी जी महाराज के मार्गदर्शन में आश्रम की महंत सर्वेश्वरी गिरि के सानिध्य में कन्या पूजन मासिक भंडारा आयोजित किया गया। महंत सर्वेश्वरी गिरि जी महाराज ने बताया कि पिछले कई वर्षो से प्रत्येक मास के जेठे रविवार को मां भगवती के स्वरूप में सैंकड़ों कन्याओं का आश्रम परिसर में पूजन किया जाता है और फल दक्षिणा के साथ जरूरतमंद कन्याओं को समय समय पर गर्मी सर्दी के वस्त्र जूते व शिक्षा के लिए पुस्तकें इत्यादि वितरित की जाती है। आश्रम में प्रतिदिन सांय को भजन संध्या कीर्तन प्रभु सुमिरन पाठ भी किया जा रहा है। महंत सर्वेश्वरी गिरि जी महाराज ने श्रद्धालु जनों को आज नवरात्रों में कन्याओं के पूजन गोमाता सेवा और शिव आराधना कर पुण्य प्राप्त विषय में आमजन को जानकारी दी और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और बताया की सत्य के मार्ग पर चलने वाला इंसान तनावमुक्त के साथ रोगमुक्त भी रहता है। इस अवसर श्री महंत बंशी पुरी जी महाराज महंत सर्वेश्वरी गिरि महाराज, महंत महेश पुरी जी के साथ यजमानों ने कन्या पूजन किया साथ ही संत समाज भी उपस्थित रहा। कन्या पूजन उत्तर भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉ. अभिषेक कुश के द्वारा संपन्न हुआ। आज के मुख्य यजमान भारत भूषण भारती, राजेंद्र गोयल लुधियाना , सचिन तायल पटियाला, मनीष रिंकू जिंदल सिन्नोर, सुनील मित्तल करनाल, गोयल परिवार सहित रहे। कार्यक्रम में षडदर्शन साधुसमाज के संगठन सचिव वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक,राघवानंद गिरि, स्वामी कर्ण पुरी, डॉ. संजीव कुमारी, सानवी, प्रधान बारु राम बंसल, गुलशन परवंदा, लव छाबड़ा अनन्य मित्तल अधिवक्ता, यश भास्कर, पुरुषोतम पुरी इत्यादि काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आश्रम में आई कन्याओं का पूजन किया गया और भंडारा प्रसाद वितरित किया गया। भगतों ने श्री महंत बंशी पुरी जी महाराज, महंत सर्वेश्वरी गिरि जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया।

विधायी प्रारूपण की गुणवत्ता बेहतर होने से लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और सुदृढ़ होंगी -विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण

हरियाणा विधान सभा के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रशिक्षण, पहले दिन हुए 4 तकनीकी सत्र

चंडीगढ़, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक 26 सितम्बर - हरियाणा विधान सभा की ओर से शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एमजीएसआईपीए) में विधायी प्रारूपण पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन 4 तकनीकी सत्र हुए। इन सत्रों में देश के जाने–माने विधि विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यू.टी. खादर फरीद तथा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा उपस्थित रहे। विस अध्यक्ष श्री कल्याण ने हरियाणा विधान सभा के इतिहास में पहली बार हो रहे इस प्रशिक्षण पहल की सराहना करते हुए कहा कि विधायी प्रारूपण की गुणवत्ता बेहतर होने से लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और अधिक

सुदृढ़ होंगी। हरियाणा विधान सभा एवं हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए आयोजित पहले सत्र में भारतीय विधि आयोग के सदस्य प्रो. डी.पी. वर्मा ने ‘विधायी प्रारूपण के मूल नियम और तकनीकें तथा विधायी भाषाओं का महत्व–सरल, द्विभाषी और बहुभाषी प्रारूपण’ विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट और सरल भाषा में कानून बनाने से न केवल जनता को समझने में आसानी होती है, बल्कि प्रशासनिक अमल में भी पारदर्शिता आती है। विधान मंडल विधि निर्माण का कार्य करते हैं। उन्हें यह देखना होता है कि जनहित में क्या अपेक्षित है। न्याय पालिका स्थापित विधि के आधार पर कार्य करती है। मूल विधायी नियमों और तकनीक में परस्पर गहरा संबंध है। दूसरे तकनीकी सत्र में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यू.टी. खादर फरीद ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार का कार्य ईश्वरीय कार्य है। कर्नाटक विधान सभा में इस भावना को प्रकट करने वाले स्लोगन लिखवाया गया है। इससे वहां के अधिकारी, कर्मचारी प्रेरित हुए हैं। विधि निर्माण करते समय हमें लोगों के दिलो–दिमाग को समझना जरूरी है। इस प्रक्रिया में जनहित को सर्वोपरि रखना होगा। जनभावना के अनुरूप काननू का निर्माण होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विधायी प्रारूपण केवल तकनीकी कार्य नहीं है, बल्कि यह जनता और सरकार के बीच विश्वास की सेतु–रेखा है। तीसरे तकनीकी सत्र में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता साक्षर दुग्गल ने ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता - विधायी प्रारूपण के लिए एक नया मिश्रित दृष्टिकोण’ विषय पर विचार रखे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों और आम नागरिकों को दी राजस्व विभाग की 4 पेपर रहित योजनाओं की सौगात

बाबैन/कुरुक्षेत्र, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के बाबैन कस्बे की उप तहसील से प्रदेश के किसानों और आम नागरिकों को राज्य सरकार के राजस्व विभाग की नई पहल के साथ 4 परियोजनाओं की सौगात दी है। इन नई परियोजनाओं के तहत किसान और आम नागरिक अब घर बैठे रजिस्ट्री, पेपर रहित निशानदेही, व्हाट्सएप चैटबोट से घर बैठे राजस्व विभाग के अपने कार्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी के साथ-साथ राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली से जमीन से सम्बन्धित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को बाबैन उप तहसील कार्यालय में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, सीमांकन पोर्टल, व्हाटसअप चैटबोट और राजस्व न्यायालय प्रबंध प्रणाली व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की 4 नई योजनाओं को लेकर तैयार की गई पुस्तिका का विमोचन भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बाबैन उप तहसील के परिसर में पौधारोपण किया और उप तहसील कार्यालय में अपने समक्ष गांव सुजरी निवासी अंकुश बंसल की पहली पेपर रहित रजिस्ट्री भी करवाई। उन्होंने गुरचरण और जरनैल सिंह से 2 कनाल भूमि खरीदी। इस रजिस्ट्री में नंबरदार अमर सिंह और पवन कुमार गवाह रहे। इस प्रार्थी अंकुश बंसल को मुख्यमंत्री ने सेल डील भी सौंपी है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने निशानदेही करने वाली जीरोवर मशीन का भी अवलोकन किया। यहां पर एसीएस एवं वित्तायुक्त डा. सुमिता मिश्रा ने मुख्यमंत्री को जीरोवर मशीन के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पेपरलेस रजिस्ट्रेशन करके राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ों पर सीधा प्रहार कर रही हैं। इस प्रणाली से मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कतई नहीं रहेगी। अब रजिस्ट्री का काम पूर्णत- डिजिटल होगी, जिसमें यह पहल मिनिमम गवर्नमेंट-मेक्सिमम गवर्नेंस की हमारी नीति का जीवंत उदाहरण है। इस पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से पर्यावरण का भी बचाव होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में डिजीटल हरियाणा कार्यक्रम अंतिम पायदान पर बैठे

व्यक्ति को सशक्त बनाने का माध्यम है। राजस्व विभाग की जिन 4 पहलों की शुरूआत की गई हैं। ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं हैं। ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की शुरुआत हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। यह विभाग सीधे जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह विभाग राजस्व प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही आपदा के समय लोगों के लिए संकटमोचक के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने समय-समय पर नई-नई तकनीकों को अपनाकर अपने कामकाज को सरल, पारदर्शी और जन- हितैषी बनाया है। आज जो पहलें हम शुरू करने जा रहे हैं, वे इसी यात्रा का नया अध्याय हैं। उन्होंने कहा कि शासन का वास्तविक अर्थ जनता की सेवा करना है। इसलिए सेवा को सरल, पारदर्शी और त्वरित होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। सरकार स्वयं नागरिक के द्वार तक पहुंचे। इसी संकल्प को और आगे बढ़ाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की इन 4 पहलों का शुभारंभ किया जा रहा है।

अब सिर्फ हस्ताक्षर और फोटो खिंचवाने आना होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की इस पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। अब रजिस्ट्री करवाने में अनावश्यक देरी नहीं होगी। इससे नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उनको केवल एक बार फोटो खिंचवाने व हस्ताक्षर के लिए तहसील जाना होगा।

सीमांकन पोर्टल से रोवर और आधुनिक जीपीएस तकनीक से होगी निशानदेही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दूसरी पहल सीमांकन (डिमार्केशन) पोर्टल के लिए की गई है। किसान और कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भूमि संबंधी विवाद गांवों की एक बड़ी समस्या है। सीमांकन पोर्टल इस समस्या का एक स्थायी और तकनीकी समाधान है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब अपनी भूमि की पैमाइश के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। रोवर और आधुनिक जीपीएस तकनीक का उपयोग करके यह प्रक्रिया अब सटीकता, गति और निष्पक्षता के साथ पूरी होगी।

व्हाटसअप चैटबोट पर 24 घंटे, 7 दिन उपलब्ध रहेगी जानकारी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि तीसरी पहल व्हाट्सअप चैटबोट है। आज हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है और व्हाट्सअप संचार का सबसे सुलभ माध्यम बन गया है। सरकार ने इस तकनीक का उपयोग जनता की सेवा के लिए किया है। नया व्हाट्सएप चैटबॉट राजस्व विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, सेवाओं की स्थिति और आवश्यक दस्तावेजों की सूची चौबीसों घंटे, सातों दिन उपलब्ध कराएगा। अब किसी भी छोटी से छोटी जानकारी के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। अब अपने मोबाइल पर, तुरंत और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह नागरिकों को सशक्त बनाने का एक माध्यम है। इससे सरकार और जनता के बीच की दूरी कम होगी। खासतौर पर गांव की जनता के लिए यह सुविधा बहुत मददगार साबित होगी।

रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम को न्याय में देरी करेगा खत्म

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चौथी पहल रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम की है। राजस्व न्यायालयों में लंबित मामले न्याय की राह में एक बड़ी चुनौती रहे हैं। न्याय में देरी, न्याय से वंचित होने के समान है। अब राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। केस की स्थिति, तारीख और आदेश ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इस सिस्टम से छोटे-छोटे मामलों में बरसों की देरी खत्म होगी। इससे न्याय प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी होगी। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम सभी राजस्व अदालतों के मामलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। यह न केवल न्यायिक पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि लंबित मामलों के त्वरित निपटान में भी सहायक होगा।

ई-पंजीकरण प्रणाली के तहत रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति पहले ही ले सकता है अपॉइंटमेंट

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के पक्षधर हैं। उन्होंने वर्ष 2014 में डिजीटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पिछले 11 वर्षों में इस कार्यक्रम के परिणाम हमारे सामने हैं। इस कार्यक्रम से आम लोग डिजीटली रूप से सशक्त हुए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। जन-सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से ई-पंजीकरण प्रणाली शुरू की थी। इसके तहत रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकता है।

सीएलयू देने की शक्तियां निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को दी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाओं और कालोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने के अधिकार मुख्यमंत्री कार्यालय के पास थे। इस व्यवस्था को खत्म किया और इसकी शक्तियां निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को दी। सीएलयू के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन है। इस प्रक्रिया से आवेदक यह भी देख सकता है कि उसकी फाइल किसके पास पहुंची है। सभी सीएलयू अब 30 दिनों में ऑनलाइन हो जाते हैं।

भू-स्वामी अपनी सम्पत्तियों और भू-रिकॉर्ड की ऑनलाइन ले सकता है जानकारी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भू-रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटलाइज करने के लिए सभी तहसीलों में समेकित हरियाणा भू-रिकॉर्ड सूचना प्रणाली लागू की गई है। इसके माध्यम से अब भू-स्वामी किसी भी समय और कहीं से भी अपनी सम्पत्तियों और भू- रिकॉर्ड की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने नई शुरू की गई चारों योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। भू-अभिलेख विभाग निदेशक डा. यशपाल ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों का स्वागत किया। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का धन्यवाद किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी, अंबाला कमिश्नर संजीव वर्मा, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, एसडीएम पंकज सेतिया, जिला अध्यक्ष तिजेंदर सिंह गोल्डी, मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी, सुभाष कलसाना, चेयरमैन डॉ गणेश दत्त, चेयरमैन जसविंदर जस्सी, चेयरपर्सन कंवलजीत कौर, चेयरपर्सन साक्षी खुराना, मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा, मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष शिव गुप्ता, सरपंच संजीव सिंगला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

हाटसअप चैटबोट भू-मित्र के माध्यम से कर सकेंगे सूचना, सर्विस और शिकायत- डा. सुमिता मिश्रा

राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने कहा कि आज बाबैन की छोटी सी तहसील से प्रदेश के हर किसान व हर नागरिक के लिए बेहतर योजनाओं की शुरू की जा रही है। बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने विभाग के सामने कुछ लक्ष्य रखे थे। इनमें कहा था कि सदियों से चली आ रही जरिफ खींच कर की जा रही पैमाइश की व्यवस्था को बदला जाए। इसी तरह रजिस्ट्री के मामले में लोगों का समय भी लग रहा है और परेशानी भी हो रही है। रेवेन्यू विभाग के काम को करने की प्रक्रिया और नई पहले की व्यवस्था पूरी तरह से अलग है। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेशभर में इन पहलों का शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही व्हाटसअप चैटबोट को भू-मित्र के नाम से शुरू करवाया गया है। इस माध्यम से सूचना, सर्विस और शिकायत कर सकेंगे। साथ ही पिहोवा तहसील से रिवेन्यू कोर्ट सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा। इससे कोर्ट में बार-बार तारिख मिलने सहित अन्य सभी प्रकार की जानकारी मुहैया होगी। अब इन योजनाओं रिवेन्यू विभाग के अधिकारियों- कर्मचारियों और नागरिकों के बीच धरातल पर काम करना होगा। नई प्रक्रिया को लागू करते समय कुछ दिक्कतें होती है, इन्हें सहयोग से दूर किया जा सकता है।

किसान केवल 1 हजार रुपए में करवा सकते हैं कृषि भूमि की निशानदेही डा. यशपाल

भू-अभिलेख विभाग के निदेशक डा. यशपाल ने मुख्यमंत्री व अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि आठ महीने पहले विभाग को निर्देश आए कि कैसे लोगों को समयबद्ध, पारदर्शी ढंग से सुविधाएं दे सके। पेपरलेस रजिस्ट्री और सीमाकंन से लोगों को बहुत फायदा होगा। पहले लोगों को सभी कागजात साथ लेकर आने होते थे, पूरा दिन तहसीलों में बैठकर अपने नंबर का इंतजार करना होता था, लेकिन अब मात्र 5 मिनट में फोटो और हस्ताक्षर के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह किसानों को पहले प्राइवेट मशीन से निशानदेही करवानी पड़ती थी, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन करके डिमार्केशन करवा सकते हैं। इस कार्य के लिए किसानों को प्राइवेट में करीब 30 हजार रुपए देने होते थे, अब किसानों से कृषि भूमि की पैमाइश के लिए मात्र एक हजार रुपए ही दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य के अनुरूप शासन के लिए कर्मचारी से कर्मयोगी तक का खाका तैयार किया

लेखक
श्री डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम
भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग के मानव संसाधन सदस्य

देश लोक प्रशासन में सुधार के अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। अब न केवल अधिकारियों के प्रशिक्षण के तरीके बदल रहे हैं, बल्कि उनकी सेवा के मायनों में भी बदलाव आ रहा है। मिशन कर्मयोगी-लोक सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस बदलाव में इंजन की भूमिका निभा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच झलकती है। 25 वर्षों से अधिक समय तक सरकार चलाने और पांच दशकों से अधिक सार्वजनिक जीवन का अनुभव रखने वाले श्री मोदी, व्यवस्थाओं के प्रति एक संचालक जैसी समझ, जड़ आदतों के प्रति एक सुधारक जैसी अधीरता, और ध्रुव तारे की तरह स्पष्ट -नागरिक-प्रथम, विकसित भारत के उद्देश्य को सामने रखते हैं।

मिशन कर्मयोगी की खासियत यह है कि यह केवल दिखावे भर के लिये मानव संसाधन सुधार नहीं है। यह देश की लोक सेवाओं की मूल्य-आधारित परिवर्तनकारी पुनर्रचना है और इसका मुख्य ध्यान प्रदर्शन पर है। यह कार्यक्रम तीन निर्णायक बदलावों को संहिताबद्ध करता है- पहला बदलाव सरकारी अधिकारियों की मानसिकता में बदलाव है, यानी स्वयं को कर्मचारी मानने से लेकर कर्मयोगी मानने तक का सफर है। दूसरा बदलाव कार्यस्थल में बदलाव है, इसमें प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी सौंपने से लेकर प्रणालीगत प्रदर्शन बाधाओं का निदान और उन्हें दूर करने तक का बदलाव शामिल है। तीसरा बदलाव सार्वजनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और उससे जुड़ी क्षमता निर्माण प्रणाली को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित बनाना है। यह संरचना स्पष्ट रूप से मोदी के इक्कीसवीं सदी के शासन की मांगों के दूरदर्शी ढांचे से उभर कर सामने आयी है।

यह जीवंत नेतृत्व का परिणाम है। मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में, मोदी ने एक समग्र सरकारी संस्कृति को बढ़ावा दिया-अलग-अलग क्षेत्रों में अलगाव को खत्म किया, मंत्रियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बहस पर बल दिया, और फाइलों को आगे बढ़ाने की बजाय सिस्टम समाधानों को प्राथमिकता दी। यह भावना महामारी के दौरान दिखाई दी, जब सरकार, उद्योग, नागरिक समाज और नागरिक स्वयंसेवकों के सभी स्तरों पर ‘टीम इंडिया’ एक साझेदारी मॉडल के रूप में आगे बढ़ी। यही सहयोगात्मक शक्ति अब जीईएम और गतिशक्ति जैसे सुधारों को संस्थागत रूप दे रही है।

उन्होंने नेतृत्व की आदतों को संरचनाओं में भी ढाला। जो चिंतन शिविर-आवासीय, पदानुक्रम-समतल विचार-मंथन सत्र-गुजरात में शुरू किए गए थे वे अब केंद्र सरकार की कार्यपुस्तिका का हिस्सा हैं। निरंतर सीखने पर उनका बल व्यक्तिगत है। अपने ज्ञान और कौशल का निरंतर विस्तार करने के अलावा, वे यह भी जांचने के लिए जाने जाते हैं कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी एक व्यापक, कभी भी और कहीं भी सीखने का ईको सिस्टम है। इसमें 3,000 से ज़्यादा स्व-प्रगति पाठ्यक्रम हैं जो सभी के लिए सुलभ हैं और सीखने को

आईजीओटी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं। संस्थागत स्मृति के साथ उनके व्यवहार में बहुत समावेशीता है। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, उन्होंने मंत्रियों से दशकों तक एक तरह से व्यवस्था से भली-भांति परिचित अपने सहायकों और अनुभाग अधिकारियों से सीखने का आग्रह किया। व्यवहार में संस्कृति परिवर्तन ऐसा ही दिखाई देता है।

जमीनी स्तर पर, सुधार की रीढ़ उद्देश्यपूर्ण तकनीक है। आईजीओटी -कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म लोकतंत्रात्मक बनाते हैं। यह सीखने को मानव संसाधन कार्यों जैसे योग्यता मानचित्रण, करियर नियोजन और मार्गदर्शन से जोड़ता है-देश को प्रदर्शन पुलिसिंग से सक्षम क्षमता की ओर ले जाता है। यह पहले से ही बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदान कर रहा है। लाखों अधिकारियों को नए कानूनी ढांचों के अनुरूप प्रशिक्षित किया गया है; देश भर में लाखों पुलिस, डॉक्टर और अन्य कर्मचारी नागरिक संपर्क को मजबूत कर रहे हैं और सेवाभाव कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं; और बड़ी संख्या में लोग एआई और आईओटी जैसी उभरती तकनीकों में प्रमाणपत्र प्राप्त कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री की ‘तकनीक-अनुकूल’ प्राथमिकता संस्थागत ताकत में परिवर्तित हो चुकी है।

दार्शनिक सार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मिशन कर्मयोगी प्राचीन सभ्यतागत ज्ञान को आधुनिक शासन-कला के साथ जोड़ता है-विकास, गर्व, कर्तव्य और एकता जैसे संकल्पों के साथ-साथ स्वाध्याय, सहकार्यता, राजकर्म और स्वधर्म (नागरिकों पर ध्यान) जैसे व्यक्तिगत गुणों को भी समाहित करता है। यह कोई पुरानी यादें नहीं हैं; यह उच्च तकनीक युग के लिए एक व्यावहारिक नैतिकता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि योग्यता चरित्र में समाहित हो।

नागरिक-केंदितता-जनभागीदारी-दूसरा स्तंभ है। प्रधानमंत्री मोदी बार-बार इस बात पर ज़ोर देते रहे हैं कि प्रत्येक सार्वजनिक निर्णय के केंद्र में नागरिक होने चाहिए। यही उनका शासन मंत्र है। व्यवहार में नागरिक सहभागिता दोतरफा समझौता बन जाती है। नीति और क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी होती है और अधिकारी अंतिम छोर पर खड़े अंतिम नागरिक की सेवा के लिए तैयार होते हैं। मिशन कर्मयोगी इस समझौते के लिए मानसिकता और तरीके विकसित करने का राज्य का साधन है।

आत्मनिर्भरता इसकी पूरक है। यह एकाकीपन नहीं है; यह खुलेपन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से प्रेरित क्षमता और आत्मविश्वास है। यही दृष्टिकोण क्षमता निर्माण के प्रयासों और माईगव जैसे प्लेटफ़ॉर्म के व्यापक प्रसार में भी दिखाई देता है, जो नागरिकों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि सह-निर्माता बनाता है। यह कथा भारत के सभ्यतागत लोकाचार में निहित है-और संस्थानों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के युग में फलने-फूलने के लिए तैयार करती है।

कार्यक्रम की संस्थागत संरचना प्रधानमंत्री मोदी की व्यावहारिकता को दर्शाती है। डिजिटल आधार और बाज़ार को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन, कर्मयोगी भारत, समन्वय के लिए एक मंत्रीमंडल सचिवालय इकाई; संरक्षक और मानक-निर्धारक के रूप में क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी); और शीर्ष-स्तरीय संचालन के लिए प्रधानमंत्री ने मानव संसाधन परिषद का नेतृत्व किया । इसकी संरचना सहयोगात्मक, लेखा-परीक्षण योग्य और परिणाम-उन्मुख है-एक ऐसा शासन ढांचा जो ‘कहीं से भी काम करने’ वाले देश के लिए उपयुक्त है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो सीखता है उसे संचित नहीं कर रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के अनुरूप, देश अपने ज्ञान, अनुभव और उपकरणों को साझा करने की तैयारी कर रहा है। इन्हें लोक प्रशासन में एक आदर्श के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण है, वहां तकनीकी व्यवधानों के बीच देशों को समान क्षमता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मॉरीशस को इस दिशा में पहले ही सहायता की पेशकश की जा चुकी है-यह एक प्रारंभिक संकेत है कि मिशन कर्मयोगी विकासशील लोकतंत्रों में एक अभ्यास समुदाय का निर्माण कर सकता है।

सीधे शब्दों में कहें तो, मिशन कर्मयोगी एक दूरदर्शी विचार को एक व्यवस्था में बदल देता है। यह प्रधानमंत्री मोदी के शासन के लंबे दायरे-उनकी सीमाओं को तोड़ने की सहज प्रवृत्ति, तकनीक के साथ उनका सहज व्यवहार, संस्थागत स्मृति के प्रति उनके सम्मान और उनकी नैतिक शब्दावली-को एक दोहराए जाने योग्य संचालन मॉडल में बदल देता है- भूमिका-आधारित मानव संसाधन; निरंतर, डिजिटल शिक्षा; नागरिक भागीदारी; और सभ्यता पर आधारित नैतिकता इसमें समाहित हैं। इस तरह आप किसी देश को भविष्य के लिए तैयार करते हैं।

अगर भारत इसी राह पर चलता रहा, तो इसका फ़ायदा सिर्फ़ तेज़ गति से आगे बढने वाली काम की फ़ाइलों और व्यवस्थित संगठनात्मक चार्ट में ही नहीं, बल्कि भरोसे में भी दिखेगा। नागरिक एक ऐसी सरकार का अनुभव करेंगे जो सुनती है, सीखती है और काम करती है। यही प्रधानमंत्री मोदी के दांव का मूल है। और यही वजह है कि मिशन कर्मयोगी, हाल के दशकों के किसी भी प्रशासनिक सुधार से ज़्यादा, अपने असली रूप में देखा जाना चाहिए। यह लोगों की सेवा करने वाले लोगों में एक पीढ़ीगत निवेश है और इसे एक ऐसे नेता ने तैयार किया है जिसने अपना जीवन लोगों की सेवा में ही लगा दिया है।

विचारों को मूर्त रूप प्रदान करना – मोदी का अंदाज

लेखक
हसमुख अधिया

नरेन्द्र मोदी की यात्रा के मूल में एक विशेष आदत: अनवरत अवलोकन निहित है। वह प्रत्?येक मुलाकात को विचारों के स्रोत के रूप में देखते हैं, चाहे वह सामान्य बातचीत हो या विदेश यात्रा। लेकिन इन्हें नवीनता या अकादमिक विचार मानने वाले अनेक लोगों के विपरीत, मोदी इनमें से प्रत्येक विचार को संभावित समस्या के मूल कारण के आधार के तौर पर परखते हैं और फिर उसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल समाधान में ढालते हैं। जिज्ञासा, विश्लेषण और प्रभावी क्रियान्वयन के इसी मिश्रण ने उन्हें जमीनी स्तर के आयोजक से एक वैश्विक राजनेता के रूप में स्थापित किया है।

वास्?तव में, मोदी के लिए सीखना कभी उम्र का मोहताज नहीं रहा। बचपन से ही, उनमें सहज जिज्ञासा थी और वे विविध कहानियों और अनुभवों को आत्मसात करते और तलाशते थे। जीवन भर उनका यही विश्वास रहा है कि जिज्ञासा हर स्तर पर को सीखने को बढ़ावा देती है। यहाँ तक कि उनकी जिम्?मेदारियाँ जब क्षेत्रीय नेतृत्व से राष्ट्रीय पद तक बढ़ गई, इसके बावजूद, ऐसी नियमित मुलाकाते उनके मन में विचारों को जन्म देती रहीं और छोटी–छोटी बातें सीख में बदल गईं, जो वर्षों बाद, ऐन कार्रवाई करने का समय आने पर ही फिर से उजागर हुईं।

किशोरावस्था में, ज्ञान की इसी ललक ने उनकी यात्रा का आगाज़ किया। पहले–पहल आध्यात्मिक साधक के रूप में और बाद में एक समर्पित संघ प्रचारक के रूप में उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की और ऐसे अनुभव बटोरे, जिन्?होंने दुनिया को देखने–समझने की उनकी दृष्टि को आकार दिया। हर बातचीत उनके लिए कुछ नया सीखने का अवसर थी।

लेकिन जो बात उन्हें दूसरों से जुदा करती है, वह यह है कि यह सूझबूझ केवल सैद्धांतिक नहीं रही; अवसर पाते ही, उन्होंने इसे क्रियान्वित किया। हालाँकि, समस्या–समाधान की यह कला अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से सामने आती रही। उदाहरण के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान, उन्होंने देखा कि कर्मचारी संगमरमर के ठंडे फर्श पर नंगे पाँव काम कर रहे थे और उन्होंने तुरंत उन कर्मचारियों के लिए जूट की चप्पलों का प्रबंध कर दिया, यह एक आसान उपाय था, जो सर्दी और आने वाली गर्मी, दोनों के लिए कारगर रहा। एक अन्य घटना में, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जापान की अपनी यात्रा के बाद, उन्होंने स्पर्शनीय मार्गचिन्ह (उभरी हुई सतह) की अवधारणा शुरु की। दृष्टिबाधित लोगों के लाभ के लिए उन्होंने इसे अहमदाबाद में लागू

करने पर ज़ोर दिया। ये संकेत उनकी एक अनवरत आदत को जाहिर करते हैं: अनदेखा कर दी गई बारीकियों को दैनिक जीवन को आसान बनाने वाले व्यावहारिक सुधारों में बदलना।

उनके कुछ विचार बीते दशकों की याद दिलाते हैं। 1993 में लॉस एंजिल्स की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने फाइनेंशियल हाई–राइजिज के समूहों का अध्ययन किया; वर्षों बाद, उन्हीं विचारों ने गुजरात में गिफ्ट सिटी को भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को केंद्रीकृत करने के केंद्र के रूप में प्रेरित किया। इसी जिज्ञासा ने अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट को आकार दिया, जहाँ उन्होंने अधिकारियों से दुनिया भर की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करवाया, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया कि अंतिम डिज़ाइन स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित रहे। उनके अनुसार, ग्?लोबल मॉडल तभी मायने रखते हैं, जब उन्हें पहले स्थानीय समुदायों की सेवा के लिए अनुकूलित किया जा सके। इस पद्धति में, कोई भी अवलोकन कभी भी सराहना किए योग्?य अलग–थलग विचार नहीं होता, बल्कि यह एक रिसोर्स बैंक की तरह होता है, जो परिस्थितियों के अनुकूल होने पर लौटकर आता है, और संग्रहीत विचारों को विशाल परियोजनाओं में परिवर्तित कर देता है।

2002 में, कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मोदी ने आपदा से निपटने में इस पद्धति को अपनाया। उन्होंने नियमित नौकरशाही मॉडलों को नकारते हुए अपनी टीम को जापान के कोबे भूकंप प्रबंधन का अध्ययन करने और उसके योजनाकारों से संपर्क करने का निर्देश दिया। लेकिन उनका विचार स्पष्ट था: मॉडलों को पूरी तरह से आयातित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, इन जानकारियों को गुजरात के लिए तत्काल आवश्यकता वाले समाधानों जैसे भूकंपरोधी आवास, सुरक्षित निर्माण पद्धतियाँ और सामुदायिक भागीदारी– में ढाला गया। भारत में यह पुनर्वास के लिए एक मानक बन गया, जिसने दिखाया कि कैसे एक संकट अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान को भारतीय पहल के साथ मिलाने का परीक्षण स्थल बन सकता है। प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने इसी क्रम को जारी रखा, दक्षिण कोरिया में नदी–सफाई परियोजनाओं का दौरा इसी इरादे से किया, कि उनसे प्राप्त सबक को नमामि गंगे में लागू किया जा सके।

भारत के भीतर से उभरने वाले विचारों के प्रति भी उन्होंने उतना ही उत्साह दिखाया है। इसका उल्लेखनीय उदाहरण नैनो यूरिया है, जो एक युवा वैज्ञानिक द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए सुझाव से उपजा नवाचार है। मोदी ने तुरंत इसकी क्षमता को पहचाना और इसके विकास पर ज़ोर दिया। आज, इसकी एक छोटी बोतल पारंपरिक उर्वरक की एक बोरी की जगह ले सकती है, जिससे लागत में कमी आती है और किसानों का बोझ कम होता है। यही खुलापन सरकारी कार्यक्रमों को भी आकार देता है: जब वित्तीय समावेशन योजना के नामकरण के लिए जनता की प्रतिक्रिया मांगी गई, तो नागरिकों ने ही 卐जन धन卐 शब्द गढ़ा। वैज्ञानिकों और आम लोगों, दोनों के नवाचारों को प्रोत्साहित करते हुए मोदी ने दिखाया कि कैसे घरेलू विचारों को राष्ट्रीय समाधानों में बदला जा सकता है।

ये कहानियाँ मिलकर मोदी के जीवन के एक अनवरत सूत्र को उजागर करती हैं। मंदिर में मामूली प्रतीत होने वाली असुविधा को दूर करने से लेकर, एक आधुनिक शहर की रूपरेखा तैयार करने, किसी तबाह क्षेत्र के पुनर्निर्माण या किसी क्रांतिकारी उर्वरक को अपनाने तक, उनकी प्रक्रिया एक समान ही रही है: स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना, लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करना और उसे पूरा करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना। 卐आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वत:卐 (प्रत्येक दिशा से कल्याणकारी विचार हमारी ओर आएँ) के भारतीय दर्शन का पालन करते हुए, मोदी हर यात्रा और संवाद से सक्रिय रूप से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और भारत को आगे बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करने का दृढ़तापूर्वक प्रयास करते हैं। अंतत:, उनका हर विचार लोगों के लिए होता है, उनके जीवन और विकसित भारत की उनकी आकांक्षाओं में निहित होता है।

लेखक एक आईएएस अधिकारी हैं, जो भारत के वित्त एवं राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।

विश्वविद्यालयों में कौशल, स्वास्थ्य और खेल पर दिया जाए ध्यान – प्रोफेसर असीम कुमार घोष

दो दिवसीय बैठक में ग्रीन कैंपस और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर हुई चर्चा

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, – हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि हरियाणा देश में खेलों के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट पहचान रखता है। विश्वविद्यालय परिसरों में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करना और छात्रों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना समय की मांग है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने विद्यार्थियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान करना चाहिए। आज यहां हरियाणा के विश्वविद्यालयों में शिक्षा, कौशल, खेल, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जोड़ने के उद्देश्य से हरियाणा राजभवन में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुलसचिवों की दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा भी शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आज के सत्र से विश्वविद्यालयों को शिक्षा, कौशल, खेल, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए दृष्टिकोण और दिशा प्राप्त हुई है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हरियाणा की सभी विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस बनाने के प्रयास करने चाहिए, ताकि स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय एक आदर्श स्थापित कर सकें।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने वर्षा और बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों के लिए पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की

तीनों राज्यों के 27 लाख से अधिक किसानों को 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित

मनदीप कौर

माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी करने की घोषणा की। यह किस्त विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के उन किसानों के लिए प्राथमिकता के आधार पर है, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के कृषि मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही किसान समूहों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। तीनों राज्यों ने हाल ही में भीषण बाढ़, भूस्खलन और फसल की व्यापक क्षति का सामना किया है, जिससे किसान परिवारों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इस संदर्भ में आज जारी पीएम–किसान योजना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तीनों राज्यों के लगभग 2.7

लाख महिला किसानों सहित 27 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में कुल 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई है। इस सहायता का उद्देश्य हाल की आपदाओं से उबरने के लिए किसानों को समय पर राहत प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान श्री शिवराज सिंह चौहान ने हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़े रहने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2,000 रुपये की किस्त से किसानों को अपनी तत्काल घरेलू जरूरतें पूरी करने, अगले बुवाई सीजन के लिए बीज और उर्वरक खरीदने और खेती फिर से शुरू करने का आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वित्तीय सहायता के अलावा यह किस्त इस बात का आश्वासन भी है कि सरकार हर किसान की परवाह करती है और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में उनके संघर्ष में कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लघु वृत्तचित्र भी दिखाया गया, जिसमें बाढ़ प्रभावित तीन राज्यों के किसानों की कठिनाइयों और इस मुश्किल घड़ी में सरकार द्वारा उनकी सहायता के लिए उठाए जा रहे कदमों को दर्शाया गया है। कृषि मंत्री ने इस महीने की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे को भी याद किया, जहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लिए क्रमश: 1500 करोड़ रुपये, 1600 करोड़ रुपये और 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सहित व्यापक राहत उपायों की घोषणा की थी। इसके अलावा, मृतकों और घायलों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता भी प्रदान की गई थी। पीएम–किसान की 21वीं किस्त का जारी होना इन उपायों पर आधारित है और जरूरत के समय में किसान परिवारों को समय पर मदद पहुंचाने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

रणदीप सुरजेवाला ने किया पीपली व थानेसर की अनाज मंडी का दौरा

सुरजेवाला ने भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री नायब सैनी पर बोला हमला

कुरुक्षेत्र, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक 27 सितंबर : हरियाणा के किसान नवरात्रि के पावन पर्व में भी मंडियों में लुट रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चुनावी वादा पीआर धान ?3,100 प्रति क्विंटल पर खरीदने का पूरी तरह खोखला साबित हो गया है। आज खरीफ सीजन के पांचवें दिन भी सरकारी खरीद शुरू होने का नाम नहीं ले रही, और किसान नमी के बहाने ?2,369 के रूक्क से भी 500 रुपये कम पर मजबूर हैं। यह %नायब झूठ% नहीं तो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज कुरुक्षेत्र जिले की पीपली व थानेसर अनाज मंडियों का दौरा किया। भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री नायब सैनी पर पर तीखा प्रहार करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नायब सैनी %नायब हैं गायब%। किसानों की मेहनत को मंडियों में लूटा जा रहा है, बाढ़ का 50 लाख एकड़ नुकसान मुआवजे के बिना सड़ रहा है, और गेहूं बुआई के लिए छक्क खाद की कालाबाजारी चरम पर है। यह भाजपा का %किसान विरोधी कुंभकर्ण नींद% है! सुरजेवाला ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले सैनी ने बड़े–बड़े जुमले उछाले कि धान का एक–एक दाना खरीदेंगे। लेकिन हकीकत में 10 जिलों की मंडियों में 5 लाख मीट्रिक टन धान पड़ा सड़ रहा है। छह जिलों में तो खरीद शुरू ही नहीं हुई, और बाकी जगहों पर रूक्क पर खरीद न के बराबर। जमीन

का खर्च ?82,000 प्रति एकड़, लेकिन धान से किसान को ?40,000 भी नहीं मिल रहा। पीआर धान ?1,900–?2,100 में, 1501 बासमती ?2,500–?2,900 में बिक रही है जबकि बाजार मूल्य ?3,500–?4,000 होना चाहिए। किसानों व आढ़तियों के साथ यह सरकारी धोखा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ में 50 लाख एकड़ फसल बर्बाद, ?7,000 प्रति एकड़ मुआवजा घोषित लेकिन एक रुपया भी नहीं पहुंचा। लाखों एकड़ में पानी भरा है, गेहूं की बुआई पर संकट, लेकिन सैनी हेलीकॉप्टर से उतरने को तैयार नहीं। पीएम मोदी ने तो हरियाणा से मुंह मोड़ लिया, बाढ़ ही नहीं आई% कहकर केंद्र से एक पैसा नहीं दिया। सुरजेवाला ने कहा कि बाजरा उत्पादकों की हालत और भी बुरी है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा में बाजरा ?2,775 एमएसपी पर खरीदा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ?2,150 से नीचे खरीद न करने का आदेश दिया। चरखी दादरी में 70,000 क्विंटल बाजरा मंडी में अटका, लेकिन भाजपा ने ठेंगा दिखा दिया। आखिर किसान कहां जाएं? यह भाजपाई जुल्म है। उन्होंने कहा कि डीएपी खाद की कमी ने गेहूं बुआई को परेशान कर दिया। सुबह 4 बजे से लाइनें लग रही, लेकिन बेरंग लौटना पड़ रहा। निजी दुकानों पर कालाबाजारी ?1,950 प्रति बैग ब्लैक में बिक रहा, जबकि सरकारी दर ?1,350 है। भाजपा सरकार को कोई फिक्र नहीं। किसानों को दिखावा और धोखा मिल रहा। भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री नायब सैनी से रणदीप सुरजेवाला ने मांग की कि किसान का धान ?2,369 और बाजरा ?2,775 प्रति क्विंटल पर बिना बहाने एक–एक दाना खरीदा जाए। निर्यात बाधाओं के चलते 1509, 1121 आदि किस्मों पर ?3,500 प्रति क्विंटल की वन टाइम खरीद की जाए। अगले 7 दिनों में ?50,000 प्रति एकड़, नष्ट मकानों–ट्यूबवेलों का पूरा हर्जाना दिया जाए। 5,000 प्रभावित गांवों में प्रत्येक एससी व बीसी परिवारों को ?50,000 मुआवजा दिया जाए व जलभराव वाले इलाकों में तुरंत पानी निकासी का प्रबंध किया जाए। डीएपी की जरूरत, उपलब्धता और कदमों का सार्वजनिक ब्योरा दिया जाए।

विरासत एएचए सांझी उत्सव का समापन 1 अक्टूबर को

सांझी की साज–सज्जा में किया जाता है लोक प्रतीकों का प्रयोग

कुरुक्षेत्र, संजीव कुमारी : विरासत दि हेरिटेज विलेज जी.टी. रोड मसाना में विरासत हेरिटेज व एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे सांझी उत्सव–2025 का समापन 1 अक्टूबर को किया जायेगा। यह जानकारी विरासत एएचए सांझी उत्सव के निदेशक अभिनव पूनिया ने दी। उन्होंने बताया कि विरासत हेरिटेज विलेज एवं एएचए संस्कृति संरक्षण के लिए परंपराओं को सहेजने के लिए पिछले काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि में सांझी लुप्त होती एक ऐसी लोककला है जिसको लोकजीवन में महिलाएं सदियों से बनाती आ रही हैं। इस लोककला को गोबर और मिट्टी से प्राकृतिक स्वरूप में बनाया जाता है। इसकी साज–सज्जा के लिए जहां एक ओर नैसर्गिक रंगों का प्रयोग होता है वहीं पर दूसरी ओर प्रतीकों के माध्यम से भी सांझी की साज–सज्जा की जाती है। लोक प्रतीक सांझी की सजावट में चार चांद लगाने का कार्य करते हैं। अभिनव ने बताया कि सांझी एक प्राकृतिक लोककला है, इसमें जो भी रंग एवं सामग्री प्रयोग होती

है वह पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। मिट्टी एवं गोबर से बनी सांझी के ऊपर गेरूए एवं सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के सितारों एवं सांझी के अंग–प्रत्यंगों को इन्हीं रंगों से सुसज्जित किया जाता है। पहले दीवार पर गोबर लगाया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी से बनी हुए सितारों एवं अंग–प्रत्यंगों से सांझी बनाई जाती है। लोककला की दृष्टि से सांझी लोकजीवन की ऐसी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें आंचलिकता के दर्शन होते हैं। संस्कृति संरक्षण केवल इतिहास को बचाने का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान और सामाजिक मूल्यों को जीवित रखने का माध्यम भी है। समाज के हर वर्ग को इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि भारत की समृद्ध संस्कृति विश्व पटल पर और अधिक उजागर हो सके।

प्रकृति संरक्षण के लिए किया जाता है लोक प्रतीकों का प्रयोग: डॉ. महासिंह पूनिया–हरियाणवी संस्कृति विशेषज्ञ डॉ. महासिंह पूनिया ने बताया कि बदलते दौर और आधुनिकता की दौड़ में जहां परंपराएँ और लोक कलाएँ धीरे–धीरे लुप्त होती जा रही हैं, वहीं संस्कृति संरक्षण को लेकर और बड़े स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सांझी बनाने के लिए अनेक लोक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर मिट्टी की चिडय़ा बनाई जाती, सांझी की सखी धुंधी बनाई जाती है। सांझी के सजने संवरने के लिए कंघा एवं शीशा बनाया जाता है, पारिवारिक उन्नती की परिचायक सीढ़ी बनाई जाती है, हवा करने के लिए बीजणा बनाया जाता है। सौम्यता एवं शीतलता प्रदान करने के लिए चन्द्रमा का निर्माण किया जाता है। रोशनी एवं जीवन के लिए सूर्य बनाया जाता है। गतिशीलता एवं उत्सुकता के लिए चिड़ियों का निर्माण किया जाता है। उत्साह एवं उल्लास का प्रतीक मोर बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाली एवं सौहार्दता का प्रतीक तोता बनाया जाता है। पारिवारिक समृद्धता के लिए कमल का निर्माण किया जाता है। शुभता के लिए स्वास्तिक चिह्न बनाया जाता है। फलने–फूलने के लिए बेल–बूटे बनाये जाते हैं। विष्णु एवं लक्ष्मी के पांव की छाप के लिए पैरों के प्रतीक बनाये जाते हैं। पावनता एवं पवित्रता के लिए कलश का निर्माण किया जाता है। डॉ. पूनिया बताया कि इसके अतिरिक्त पशु धन की खुशहाली के लिए गाय एवं बैल बनाये जाते हैं। सांझी के पैरों में जौ बीजे जाते हैं जो पारिवारिक उन्नति का परिचायक है। इस प्रकार लोकजीवन में सांझी स्वयं दुर्गा एवं शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोडऩा बेहद आवश्यक है। इसलिए सांझी उत्सव के साथ– साथ अन्य आयोजन भी संस्कृति संरक्षण के लिए समय–समय पर किये जाने अति आवश्यक हैं।

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन 2025 का किया उदघाटन

ब्रह्माकुमारीज़ ने समाज, धर्म और देश के लिए त्याग, तपस्या और समर्पण किया – राज्यपाल

राजस्थान, ब्रह्मा कुमारीज़ आश्रम, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक = राज्यपाल बोले– विश्व में ब्रह्माकुमारीज़ जैसा महिलाओं का इतना बड़ा दूसरा संगठन नहीं मिलेगा, समाज में शांति, एकता और विश्वास को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है।

आबू रोड (राजस्थान) ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान के मीडिया विंग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन 2025 का शनिवार को विधिवत आगाज़ हो गया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इसमें देशभर से प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, रेडियो और वेब मीडिया से जुड़े 1500 से अधिक पत्रकार, संपादक और संवाददाता भाग ले रहे हैं। चार दिन तक चलने वाले इस महासम्मेलन में शांति, एकता और विश्वास विषय पर करेंगे मंथन–चिंतन किया जाएगा।

शुभारंभ पर मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि मुझे यहां आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। समाज में शांति, एकता और विश्वास को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ भी कहते हैं। मीडिया लोकतंत्र की जड़ों को सींचकर सदा हरा रखने का कार्य करता है। हमारे भारत के लोगों के रक्त में ही लोकतंत्र है।

चन्द्रगुप्त के राज्य में पाटलिपुत्र में नगर पंचायत में 30 सदस्य चुनकर आते थे। मैंने इसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू जी की किताब भारत एक खोज में पढ़ा। लोकतंत्र में जो चुनकर आते हैं, जाति के आधार पर नहीं, विचार और देशहित के आधार पर चुनाव लड़े तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। मीडिया को इस पर फोकस करना चाहिए।

संस्कृति बचाने का कार्य कर रही है ब्रह्माकुमारीज़।

राज्यपाल ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज़ एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। प्राचीन भारतीय संस्कृति ज्ञान का प्रचार–प्रसार करता रहा है। ब्रह्माकुमारीज़ संस्था महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था नशामुक्ति, पर्यावरण जागरण, अंधविश्वास दूर करने का भी काम कर रही है। ब्रह्मा बाबा ने इसकी स्थापना की। उनका हीरे का व्यापार था। ब्रह्माकुमारीज़ गांव–गांव में जाते हैं। लोगों को शांति और तरक्की का रास्ता बताते हैं। विश्व में महिलाओं का इतना बड़ा संगठन नहीं है, जितना ब्रह्माकुमारीज़ का है। ब्रह्माकुमारीज़ संस्कृति बचाने का कार्य कर रही है।

ब्रह्माकुमारीज़ ने त्याग, तपस्या और समर्पण किया है। ये देश, धर्म, समाज के लिए समर्पण किया है।

सनातन धर्म ने किसी पर टिप्पणी नहीं की।

राज्यपाल बागड़े ने कहा कि भारत की संस्कृति विश्व की पहली संस्कृति है। हजार वर्षों से ज्यादा समय तक हमारी संस्कृति को छिन्न–भिन्न करने की कोशिश की गई है। मैकाले ने हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए वर्ष 1835 में जो शिक्षा पद्धति लागू की थी। विश्व में जब कुल 6 विश्वविद्यालय थे, उस समय हमारे पास नालंदा और तक्षशिला जैसे दो विशाल विश्वविद्यालय थे। जजिया कर लगाया गया, धर्म परिवर्तन किया गया। लेकिन हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई, बल्कि तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि हमारे यहां योगी, महात्मा हुए। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। हम सर्वधर्म को मानते हैं। सनातन धर्म ने किसी पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन हमारे बारे में टिप्पणी की जाती है।

हम किसी की शांति भंग नहीं करेंगे।

राज्यपाल ने कहा कि किसी ने हमारी शांति बिगाड़ने की कोशिश किया तो उसको भी छोड़ना नहीं, ये बात हमें ध्यान रखना होगा। हम किसी की शांति भंग नहीं करेंगे।

श्रीमती सावित्री ठाकुर ने पंजाब के होशियारपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

पंकज

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने पंजाब के होशियारपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित किसानों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीणों से भी बातचीत की। श्रीमती सावित्री ठाकुर ने गंधूवाल, फतकुल्ला, अब्दुल्लापुर, हलेड़ जनार्दन, सालोवाल, मोतला, कौलियां–418 मेहताबपुर में किसान प्रतिनिधिमंडलों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों के साथ बैठकें कीं और ब्यास नदी पर बने राड़ा पुल (मंडेरिया) का भी निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बार–बार आने वाली बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए राहत और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुश्री ठाकुर ने बताया कि सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 26 सितंबर को ही पीएम–किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी है। सुश्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और क्षेत्र में बाढ़ संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा।

मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी के निधन पर परिवार से की मुलाकात

रमन कुमार

जालंधर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। शनिवार को मॉडल टाऊन स्थित उनके आवास पर पहुँचकर चुघ ने परिवार के प्रति अपनी गहन संवेदनाएं प्रकट कीं। तरुण चुग ने कहा कि जवान बेटे का इस तरह असमय चला जाना परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में पूरा भाजपा परिवार मोहिंदर सिंह केपी और उनके परिजनों के साथ खड़ा है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील शर्मा, प्रदेश महामंत्री राकेश राठौर, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, सरबजीत सिंह मक्कड़, प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट अमित तनेजा, जिला महामंत्री अशोक सरीन हिक्की, राजेश कपूर, जिला मीडिया इंचार्ज तरुण कुमार, सन्नी शर्मा, रमन पब्बी, गौरव मेहे, अमरजीत सिंह अमरी, ललित बब्बू, जॉर्ज सागर, हिमांशु शर्मा, गौरव राय आदि भी मौजूद रहे।

भविष्य की चुनौतियों और तकनीकी बदलावों पर देना होगा ध्यान-सैनी

कहा, अच्छे और स्पष्ट कानून लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली ताकत

कैप्टन सुभाष चंद्र

चंडीगढ़, – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधायी ड्राफ्टिंग केवल तकनीकी अभ्यास नहीं, बल्कि लोकतंत्र को अधिक सशक्त, प्रभावी और जनता के करीब लाने का एक माध्यम है। अच्छे और स्पष्ट कानून ही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली ताकत होते हैं। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि ड्राफ्ट बनाते समय भविष्य की चुनौतियों और तकनीकी बदलावों का ध्यान भी रखा जाए। मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा द्वारा लोकसभा की संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के सहयोग से चंडीगढ़ सेक्टर–26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में विधायी प्रारूपण एवं क्षमता संवर्धन विषय पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष श्री यू टी खादर फरीद, हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण लाल मिड्ढा उपस्थित रहे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा को और अधिक सरल, जीवंत तथा वर्तमान समय की मांग के अनुरूप बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी सफलता केवल चुनावी प्रक्रिया पर नहीं टिकी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे कानून कितने प्रभावी, स्पष्ट और जन हितैषी हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ उसकी विधायिका होती है और विधायिका की वास्तविक ताकत उसके द्वारा बनाए गए कानूनों में निहित होती है। इन कानूनों का प्रारूप आप तैयार करते हैं। इसलिए, आपका वर्तमान हालात और तकनीक से परिचित रहना जरूरी है।

मोदी का शासन–गुजरात मॉडल से भारतीय मॉडल तक

लेखक
श्री डॉ. मनसुख एल मांडविया ,
केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने वाले बहुत ही कम नेताओं ने किसी राज्य में मुख्यमंत्री का दायित्व भी संभाला है। देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री 'राष्ट्रीय' स्तर के नेता रहे हैं और उनके पास संघीय स्तर पर काम करने का अनुभव बहुत ही कम रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इसके चंद अपवादों में से एक हैं। जब श्री नरेन्द्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो वे अपने साथ गुजरात में एक दशक के राज्य–स्तरीय शासन से विकसित हुए कामकाज के एक नए दर्शन को लेकर आए। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने इस बात को बारीकी से देखा कि योजनाएं अंतिम छोर पर क्यों विफल या सफल होती हैं और फिर एक ऐसे दृष्टिकोण को परिष्कृत किया जिसने उन्हें शासन के केन्द्र में महज नीति–निर्माण के बजाय क्रियान्वयन को रखने वाला पहला प्रधानमंत्री बनाया। बिजली से लेकर बैंकिंग और कल्याण से लेकर बुनियादी ढांचे के मामले में, इस दर्शन ने तब से आज तक भारतीय राज्य द्वारा अपने नागरिकों की सेवा करने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित किया है।

अनुभव के आधार पर विकसित क्रियान्वयन–नीतिगत केन्द्रबिंदु के रूप में क्रियान्वयन में श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ विश्वास को, बिजली क्षेत्र से संबंधित उनके दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। गुजरात में, उन्होंने देखा कि गांवों में खंभे और लाइनें तो हैं, लेकिन वास्तव में बिजली नदारद है। इसका समाधान उन्होंने ज्योतिग्राम योजना के रूप में निकाला, जिसके तहत फीडरों को अलग किया गया ताकि घरों को 24 घंटे बिजली मिल सके और खेतों को बिजली का एक निश्चित हिस्सा मिल सके। प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के जरिए इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इस योजना के जरिए 18,374 गांवों को भरोसेमंद तरीके से बिजली उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2023 तक आते – आते, बिजली की यही आपूर्ति सामूहिक रूप से 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान करने वाले देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की रीढ़ बन गई।

बैंकिंग क्षेत्र में भी इसी सिद्धांत को फिर से दोहराया गया। कागजों में तो ग्रामीण परिवारों के बैंक में खाते थे, लेकिन व्यवहार में वे निष्क्रिय थे। जन–धन ने इस स्थिति को बदल दिया। आधार और मोबाइल फोन को व्यक्तिगत बैंक खातों से जोड़कर, एक कमजोर पड़ी व्यवस्था को सीधे धन हस्तांतरण की बुनियाद बना दिया गया। इससे धन बिना किसी बिचौलिए के नागरिकों के हाथों में पहुंचा, बर्बादी पर लगाम लगी और सरकारी खजाने को भारी रकम की बचत हुई।

इसके बाद आवास क्षेत्र की बारी आई। प्रधानमंत्री आवास योजना ने भुगतान को निर्माण कार्यों से जोड़ा, उनकी निगरानी के लिए जियो–टैगिंग का इस्तेमाल किया और बेहतर डिजाइन पर जोर दिया। पिछली सरकारों के अधूरे घरों के उद्घाटन के चलन को पलटते हुए, पहली बार लाभार्थियों को पूरी तरह निर्मित और रहने लायक घर मिले।

राजकोषीय संवाद को संस्थागत रूप दिया और एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया।

बल्कि भारत की विकास गाथा में हितधारक के रूप में भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

उत्पादकता के रूप में कल्याण–श्री नरेन्द्र मोदी के लिए, कल्याणकारी योजनाएं हमेशा

फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में संघीय प्रणाली–गुजरात ने श्री नरेन्द्र मोदी को यह भी दिखाया कि प्रगति किस प्रकार केन्द्र और राज्य के बीच समन्वय पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय स्तर पर, यह सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद का दर्शन बन गया।

दशकों से अटके पड़े वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को राज्यों के साथ आम सहमति बनाकर पारित किया गया। जीएसटी परिषद ने

इसके अलावा, उन्होंने राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले केन्द्रीय करों का हिस्सा बढ़ाया। इससे राज्यों को अपनी प्राथमिकताएं तय करने में ज्यादा वित्तीय गुंजाइश एवं स्वायत्तता मिली। साथ ही, उन्होंने व्यापार में सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करके और सुधारों को पुरस्कृत करके प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया। इन बदलावों ने राज्यों को न सिर्फ धन प्राप्त करने वाले के रूप में,

बुनियादी ढांचे के मामले में, गुजरात के बीआईएसएजी मानचित्रण से संबंधित प्रयोगों को पीएम गति शक्ति के रूप में विस्तारित किया गया, जहां 16 मंत्रालय और सभी राज्य अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1,400 परियोजनाओं की योजना बना रहे हैं। इससे अनुमोदन में लगने वाले समय में कमी आ रही है और क्रियान्वयन में सामंजस्य स्थापित हो रहा है।

उत्पादकता से जुड़ा निवेश रही हैं जिनका उद्देश्य इनके लाभार्थियों को सशक्त बनाना है। गुजरात के कन्या केलवणी नामांकन अभियान ने महिला साक्षरता को 2001 के 57.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 2011 तक 70.7 प्रतिशत कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर, इसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया। इस कार्यक्रम का संबंध बाल लिंगानुपात में सुधार से है, जो 2014 के 918 से बढ़कर 2023 तक 934 हो गया। लड़कियों के स्कूल जाने से उनकी शादी देर से होती है, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है और दीर्घकालिक उत्पादकता बढ़ती है। इससे वे वेतनभोगी कार्यबल में प्रवेश कर सकी हैं और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले रही हैं। मातृ स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखा गया। गुजरात की चिरंजीवी योजना ने संस्थागत प्रसवों पर सब्सिडी दी, जिससे मृत्यु दर में कमी आई। केन्द्रीय स्तर पर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने मातृत्व लाभ और पोषण को जोड़ा। इससे तीन करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता मिली। इसका मार्गदर्शक विचार एक ही था- सामाजिक व्यय से निर्बलता में कमी आनी चाहिए, विकल्प बढ़ने चाहिए और भावी कार्यबल की क्षमता बढ़नी चाहिए।

निवेशकों और नागरिकों का विश्वास–शायद, गुजरात मॉडल का सबसे सूक्ष्म प्रभाव मानसिकता में बदलाव है। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलनों ने दिखाया कि कैसे निरंतर जुड़ाव धारणाओं को बदल सकता है, एक राज्य को निवेशकों की नजर में एक विश्वसनीय निवेश गंतव्य बना सकता है और नौकरशाहों को व्यवसाय के अनुकूल बना सकता है। इसी अनुभव ने 'मेक इन इंडिया' को आकार दिया, जिसने सुव्यवस्थित मंजूरियों, भूमि गलियारों और बुनियादी ढांचे की तैयारी के जरिए विश्वसनीयता को प्राथमिकता दी। वर्ष 2014 और 2024 के बीच, भारत ने 83 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित किया, जो इसकी कार्यान्वयन क्षमता और दीर्घकालिक विश्वसनीयता में भरोसे का संकेत देता है।

नागरिकों के स्तर पर भी उम्मीदें बदल गईं। पहले, योजनाओं का मूल्यांकन घोषणाओं से होता था। आज, आम भारतीय यह मानकर चलते हैं कि सरकार द्वारा समर्थित बिजली, शौचालय, बैंक खाते, सब्सिडी वाली गैस जैसी आवश्यक वस्तुएं वास्तव में उन तक पहुंचेंगी। इस तरह की चुपचाप की गई सेवाओं की आपूर्ति और सुविधाओं के सामान्यीकरण ने एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किया है जहां वादों को उनके क्रियान्वयन से मापा जाता है, न कि उनके इरादों से। कई मायनों में, यह बढ़ी हुई उम्मीद गुजरात मॉडल की सबसे ठोस विरासत है।

विकसित भारत 2047 की ओर–'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' महज एक नारा भर नहीं है। इसकी छाप रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देती है- बिजली अब लक्जरी नहीं रही, कल्याण सीधे तौर पर उपलब्ध हो रहा है, बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं डिजिटल समन्वय से बनाईं जा रही हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा दिखावे के बजाय मापने योग्य नतीजों की दृष्टि से डिजाइन की गई है। यह अब एक ऐसा भारतीय मॉडल है जिसने शासन को अंतिम छोर तक पहुंचाया है और देश के कोने – कोने में जनजीवन को प्रभावित किया है।

जब भारत 2047 तक विकसित भारत बनने का अपना लक्ष्य हासिल करेगा, तो ऐसा इसलिए संभव हो सकेगा क्योंकि एक प्रधानमंत्री ने शासन को ही नए सिरे से परिभाषित किया है। क्रियान्वयन को प्रशासन की कसौटी बनाकर, उन्होंने भारत की विशाल मशीनरी को वादों से हटाकर काम करने वाली मशीनरी में बदल दिया है। यही छाप, जिसका परीक्षण पहले गुजरात में हुआ और जो फिर पूरे देश में फैला, श्री नरेन्द्र मोदी की निर्णायक विरासत है।

हिमाचल प्रदेश से नरेन्द्र मोदी का अटूट रिश्ता

लेखक
श्री प्रेम कुमार धूमल
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जीवन यात्रा – एक समर्पित कार्यकर्ता से लेकर देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक – भारत के विभिन्न अंचलों से उनके गहरे जुड़ाव की कहानी है। इन जुड़ावों में से एक विशेष व्यक्तिगत, राजनीतिक और आध्यात्मिक संबंध हिमाचल प्रदेश से रहा है। देवभूमि, वीरभूमि और अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य की धरती। देश की बागडोर संभालने से बहुत पहले ही, नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल की पवित्र वादियों पर अपनी छाप छोड़ दी थी।

मोदी का हिमाचल से औपचारिक जुड़ाव वर्ष 1994 में हुआ, जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया। नियुक्ति से पहले भी उनकी हिमाचल यात्राएँ आध्यात्मिक साधना और स्थानीय संस्कृति से गहरे संपर्क का माध्यम रही थीं। वे शिमला के जाखू और संकटमोचन मंदिरों में अक्सर जाया करते थे और मार्ग में बंदरों को खिलाने के लिए चना और गुड़ अपने साथ रखते थे – यह उनके जीवों एवं प्रकृति के प्रति करुणा भाव का परिचायक था।

1998 का विधान सभा चुनाव नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं हिमाचल से उनके जमीनी जुड़ाव का परिचायक रहा। उस दौर में न सोशल मीडिया था और न आधुनिक प्रचार साधन, फिर भी उन्होंने कहीं यात्राएँ निकालीं और जनसंपर्क के अभिनव तरीके खोज निकाले एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाया। साथ ही स्थानीय संस्कृति को सम्मान देते हुए अनोखे स्वागत द्वार बनवाए। चंबा में उनकी ही पहल पर बना %गद्दी शॉल गेट% न सिर्फ स्थानीय गौरव का प्रतीक बना, बल्कि भाजपा का संदेश सीधे जनता के दिल तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ। हिमाचल से नरेन्द्र मोदी का जुड़ाव केवल संगठन और राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ की प्रकृति और लोगों से उनका गहरा आत्मीय संबंध भी समय–समय पर सामने आया है। नरेन्द्र मोदी अकसर हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव के दर्शन करने को जाते थे, जो वहाँ के स्थानीय देवता हैं। मार्ग में वह ग्रामीणों से सहजता से बातचीत करते और उनके अनुभवों व परिस्थितियों को समझने में रुचि दिखाते थे। मंदिर पहुँचने के बाद मोदी न केवल दर्शन करते, बल्कि आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लिया करते थे। उन्होंने हिमाचल भाजपा संगठन को मजबूती और नई ऊर्जा देने में अहम भूमिका निभाई। कार्यकर्ताओं को राजनीति में अधिक अनुशासित, संगठित और गंभीर बनाने का श्रेय भी उन्हें जाता है। पुराने कार्यकर्ता याद करते हैं कि प्रभारी के रूप में उन्होंने सबसे पहले

प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, जो पहले आधे दिन की औपचारिक प्रक्रिया हुआ करती थी, उसे दो दिन की आवासीय पद्धति में बदल दिया। यही कदम संगठन को सशक्त करने की मजबूत नींव बना। उन्होंने हिमाचल के भाजपा संगठन को मजबूत बनाने और उसमें नई ऊर्जा का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को राजनीति में अधिक व्यवस्थित और गंभीर दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार किया। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता स्मरण करते हैं कि प्रभारी के रूप में आते ही उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, जो पहले केवल आधे दिन की औपचारिकता होती थी, उसे दो दिन का आवासीय कार्यक्रम बनाकर संगठन को मजबूत करने की ठोस नींव रखी। उन्होंने हिमाचल संगठन में कार्यकर्ताओं से सहयोग लेकर कार्य करने की परंपरा की शुरुआत की, जिसका जीवंत उदाहरण शिमला का कार्यालय %दीपकमल% है। इसका निर्माण और उद्घाटन उनके प्रभार काल में हुआ, जिसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी माता जी उनको खर्च करने के लिये जो पैसे देती थी, प्रदेश कार्यालय निर्माण के लिये उन्होंने वो पैसे पार्टी को दे दिये जिसके कारण अन्य कार्यकर्ता भी योगदान देने के लिये प्रेरित हुये। उन्होंने न केवल कार्यालय के निर्माण में मार्गदर्शन और सहयोग दिया, बल्कि हिमाचल के कार्यकर्ताओं को इसे कंप्यूटर के उपयोग के साथ आधुनिक स्वरूप देने के लिए भी प्रेरित और प्रशिक्षित किया। जब 1998 में हिमाचल विधानसभा समय से पहले भंग हुई, तब मोदी की राजनीतिक सूझबूझ ने सबको चकित कर दिया। उन्होंने भाजपा और हिमाचल विकास कांग्रेस (एचवीसी) के बीच गठबंधन कराया, निर्दलीय विधायक का समर्थन सुनिश्चित किया और यहाँ तक कि कांग्रेस नेता ठाकुर गुलाब सिंह को स्पीकर पद के चुनाव में उतरने के लिए तैयार कर लिया। इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस की संख्या घटी और प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा–एचवीसी सरकार का गठन संभव हो सका। यह उनके अद्वितीय रणनीतिक कौशल का प्रमाण था। हिमाचल से उनका संबंध केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा। यहाँ से मिली सीख को उन्होंने आगे भी लागू किया। सोलन की मशरूम खेती को उन्होंने बाद में गुजरात में प्रोत्साहन दिया। विश्वविद्यालयों में रक्षा और सामरिक अध्ययन शुरू करने का सुझाव दिया, ताकि हिमाचल की सैनिक परंपरा को शैक्षिक आधार मिले। नरेन्द्र मोदी ने पैराग्लाइडिंग करना भी हिमाचल प्रदेश से ही सीखा। राजनीति से परे, मोदी सदैव हिमाचल को %देवभूमि% मानते रहे। वे पहाड़ी मंदिरों में पेड़ों के नीचे बैठकर लंबे समय तक ध्यान साधना करते थे। प्रकृति और ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था उनके जीवन और कार्यशैली दोनों में झलकती थी। वे हिमाचली भोजन के विशेष शौक़ीन हैं – मंडी की सेपू बड़ी, चंबा का मधरा और कांगड़ा की धाम उनकी पसंदीदा व्यंजनों में गिने जाते हैं। स्थानीय संस्कृति के प्रति यह आत्मीयता उन्हें हिमाचलवासियों के और करीब लाती है। उनकी स्मरण शक्ति भी इस जुड़ाव को और विशेष बनाती है–वर्षों पुराने कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को वे आज भी नाम लेकर पहचानते हैं। 2017 में शिमला के एक कार्यक्रम में उन्होंने मंच से कई पुराने साथियों को नाम लेकर संबोधित किया और कार्यक्रम के बाद इंडियन कॉफी हाउस पहुँचकर वहाँ की कॉफी का आनंद लिया, जिसका जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में भी किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान सोलन में उन्होंने मंच से पुराने दिनों को याद करते हुए मनोहर जी के चनों का भी उल्लेख किया। ऐसे प्रसंग यह दर्शाते हैं कि हिमाचल से नरेन्द्र मोदी का रिश्ता केवल कर्तव्य तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी स्मृतियों, रुचियों और जीवन के अनुभवों का हिस्सा है–और इस रिश्ते के और भी पहलू समय–समय पर सामने आते रहते हैं। आज प्रधानमंत्री के रूप में वे हिमाचल को विशेष प्राथमिकता देते हैं–चाहे वह रोहतांग टनल का निर्माण हो या पर्यटन एवं आधारभूत ढाँचे का सुदृढ़ीकरण। हिमाचल ने नरेन्द्र मोदी को अपनेपन, विश्वास और सीख दी, और बदले में मोदी ने हिमाचल को नई ऊर्जा, विकास और गौरव की पहचान दी। यही रिश्ता इस अनोखे अध्याय को पूर्णता भी देता है और भविष्य के लिए संभावनाओं का द्वार भी खोलता है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती हरियाणा में अंत्योदय उत्थान और नारी शक्ति को रही समर्पित

एस. के. सक्सैना

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना मोबाइल ऐप किया लॉन्च

चंडीगढ़, 25 सितंबर – हरियाणा सरकार ने अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को विकास, अंत्योदय उत्थान और नारी शक्ति को समर्पित करते हुए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं और परियोजनाओं की सौगात जनता को दी। इस अवसर पर वीरवार को जिला पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की शुरुआत की और योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने आवेदन के समय आने वाली समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 18001802231 और हेल्पलाइन नंबर 01724880500 भी लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान ही योजना के तहत पात्र पांच महिलाओं का लाइव पंजीकरण भी करवाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोबाइल ऐप लॉन्च होने के कुछ समय के भीतर ही लगभग 50 हजार महिलाओं ने अपने मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड किया है और लगभग 8,000 महिलाओं ने आवेदन किया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात देते हुए 326.25 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं का भी उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में 78.04 करोड़ रुपये की लागत के 31 उद्घाटन और 78.12 करोड़ रुपये की लागत की 97 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं। इसके अलावा 80 करोड़ 72 लाख रुपये की लागत से 10 स्वास्थ्य संस्थाओं का नवीनीकरण भी किया गया है। साथ ही, लोक निर्माण विभाग व शहरी स्थानीय निकाय की एक–एक परियोजना का शिलान्यास भी किया गया है, जिनकी लागत 89 करोड़ 37 लाख रुपये है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास की योजनाओं को अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर हरियाणा सरकार समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शारदीय नवरात्रों और कर्मयोगी व राष्ट्रनायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि %राष्ट्र तभी महान बन सकता है, जब उसकी नारी सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानित होगी। हरियाणा सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि महिलाएं और बेटियां आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर हो और समाज की मुख्य धारा में भाग लें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू किया जा रहा है।

बाबा लाधी शाह सरकार का जन्मदिवस समारोह

सोनू, रविंदर

रत्नगढ़ में बाबा मेर शाह के पवित्र स्थान पर बाबा लाधी शाह सरकार का जन्मदिवस अत्यंत श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में भक्तों का उत्साह देखने लायक था। समारोह की शुरुआत दोपहर 12 बजे झंडा और चादर की रस्म से हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपनी आस्था प्रकट की। इसके पश्चात 1 बजे से भंडारे का आयोजन किया गया, जो रत्नगढ़ सहित आसपास के गाँवों के लिए खुला था। भंडारा देर रात तक चलता रहा और हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। रात 8 बजे से सूफी समागम का आयोजन हुआ, जिसमें देश के प्रसिद्ध कलाकारों ने भाग लिया। अमृतसर से आए कव्वाल अशरफ साबरी ने अपनी शानदार प्रस्तुति से माहौल को भक्तिमय बना दिया। पठानकोट से पवन और संदीप पार्टी ने भी सूफियाना रंग बिखेरा। इससे पहले, हंसराज हंस जी के प्रिय शिष्य श्री मुमताज हंस जी ने अपनी प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस भव्य आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय बदन और प्रेम कुमार शर्मा, जो रत्नघर के सरपंच हैं, उपस्थित रहे।

सेवा कार्यों में सेवादार शालू रत्नगारिया और अनिल रत्नगारिया ने विशेष योगदान दिया। यह आयोजन बाबा लाधी शाह सरकार की शिक्षाओं और सूफी परंपरा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक रहा, जिसमें श्रद्धालुओं ने एकता, सेवा और भक्ति का संदेश दिया

धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आगमन पर लगने वाली प्रदर्शनी में नजर आएंगे सुधारों के सकारात्मक प्रभाव -पंकज नैन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को आएंगे कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक 27 सितंबर ः अंबाला रेंज आईजी पंकज नैन ने कहा कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आगमन पर लगने वाली प्रदर्शनी में सुधारों के सकारात्मक प्रभाव नजर आएंगे। कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्रीकृष्ण ने न्याय के लिए गीता का उपदेश दिया था। अब कुरुक्षेत्र से ही नए आपराधिक कानूनी के बारे में ऐतिहासिक कार्यक्रम 3 अक्टूबर को केडीबी मेला ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है।

अंबाला रेंज आईजी पंकज नैन शनिवार को केडीबी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इससे पहले आईजी पंकज नैन, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों ने 3 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह महत्वपूर्ण प्रदर्शनी 4–5 दिनों तक चलेगी, जिसे अधिवक्ता, छात्र, अभिभावक और आम नागरिक शामिल होकर आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए बदलावों को समझ सके।

उन्होंने कहा कि नए कानून से हुए परिवर्तन और उपलब्धियों को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें 7 अलग–अलग विभागों की भूमिका को भी दर्शाया जाएगा। इस प्रदर्शनी को 10 भागों में विभाजित किया गया है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रुम में सूचना मिलने संबंधी प्रक्रिया होगी, सीन ऑफ क्राइम में घटना का परीक्षण दर्शाया जाएगा। इसी तरह अस्पताल में पोस्टमार्टम व इमरजेंसी की स्थिति दिखाई जाएगी, सीएफएसएल में रिपोर्ट तैयार की प्रक्रिया समझाई जाएगी।

आईजी पंकज नैन ने कहा कि पुलिस स्टेशन में काम करने का तरीका बताया जाएगा, लीगल एड के तहत आरोप पत्र तैयार करने के नियम होंगे। इसी तरह जेल से दया याचिका तथा कोर्ट में न्यायायिक फैसला होगा। इसके बाद पॉलिसी स्कीम और अंत में नए न्याय संहिता कानूनी जस्टिस की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए कानूनों पर व्याख्यान और पैनल चर्चा का आयोजन किया जाए, जिसमें कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो।

आईजी पंकज नैन ने कहा कि प्रदर्शनी में वास्तविक जीवन के उदाहरणों को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए जहां इन कानूनों के लागू होने के बाद जघन्य अपराधों का अति शीघ्र समाधान किया गया हो। इससे लोगों को इन सुधारों के सकारात्मक प्रभाव को देखने में मदद मिलेगी। इस प्रदर्शनी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के माध्यम से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में नागरिकों को जागरूक और शिक्षित करना है।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को कामों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो अपनी–अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। समय पर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में दूसरे जिलों से करीब 450 बसों से नागरिकों, कर्मचारियों व अन्य लोगों को पहुंचना है। बसों के पार्किंग की पुलिस द्वारा व्यवस्था की जानी है।

पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम में मुख्य स्थानों के लिए जिला प्रशासन द्वारा पास जारी किए जाएंगे। बिना पास वाले व्यक्तियों की चिन्हित स्थानों पर एंट्री नहीं होगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश सरकार की एक साल की उपलब्धियां को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, एसडीएम शाश्वत सांगवान, एसडीएम पिहोवा अभिनव सिवाच, एएसपी प्रतीक गहलोत, सीटीएम आशीष कुमार,जिला न्यायवादी मेनपाल, उपजिला न्यायवादी जेबी गोयल, उपजिला न्यायवादी डा. चंद्रमोहन, सीएमओ डॉ सुखबीर, जीएम रोडवेज शेर सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक, डीआईओ विनोद सिंगला सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

विधायी प्रारूपण में एआई के गुर भी सीखेंगे अधिकारी

विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने मेगसिपा पहुंचा लिया तैयारियों का जायजा

चंडीगढ़, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक ः हरियाणा विधान सभा सचिवालय की ओर से विधायी प्रारूपण पर शुक्रवार से शुरू होने वाले कार्यक्रम के सिलसिले में वीरवार को विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एमजीएसआईपीए) पहुंच तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लोक सभा के संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) के सहयोग से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधान सभा और हरियाणा सरकार के विधायी प्रारूपण से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण विधान सभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद

रहेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार सुबह 10 बजे होगा। उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। इनमें पहला व्याख्यान भारतीय विधि आयोग के सदस्य प्रो. डी.पी. वर्मा का रहेगा। यह व्याख्यान विधायी प्रारूपण के मूल नियम और तकनीकों पर आधारित रहेगा। इसमें विधायी भाषा पर भी प्रकाश डाला जाएगा। दोपहर बाद कर्नाटक विधान सभा अध्यक्ष यू.टी. खादर फरीद संबोधित करेंगे। उनके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता साक्षर दुग्गल 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता ः विधायी प्रारूपण के लिए एक नया मिश्रित दृष्टिकोण' विषय पर व्याख्यान देंगे। 'अधिनियमों की संरचना और प्रारूप ः अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक/दीर्घ शीर्षक/प्रस्तावना' विषय पर दिल्ली ज्यूडिशियल अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) बी.टी. कौल प्रकाश डालेंगे। इसके बाद प्रो. कौल 'संविधि के प्रकारः वैधानिक व्याख्या के सामान्य नियम और सिद्धांत' विषय लेंगे। 27 सितंबर को समापन समारोह समेत 5 सत्र रहेंगे। इस दिन पहले सत्र में लोक सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव रहे रवींद्र गरिमेला 'विधान निर्माण में विधायी समितियों की भूमिका' विषय पर संबोधित करेंगे। 'विधायी प्रारूपण के लिए संवैधानिक प्रावधान (संविधान का अनुच्छेद 14) और व्याख्या के लिए न्यायिक दृष्टिकोण' विषय नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के विधि विभाग के प्रो. असद मलिक लेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग में प्रो. अनुराग दीप 'विधायी प्रारूपण पर प्रशासनिक कानून के प्रमुख सिद्धांत और व्यावहारिक प्रारूपण अभ्यास' विषय लेंगे। हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव रहीं केशनी आनंद अरोड़ा 'प्रशासन में नैतिकता और मूल्य' पर व्याख्या देंगी।

हरियाणा में भाजपा ने वादा निभाया, पंजाब में मान सरकार का वादा बना छलावा-डॉ. सुभाष शर्मा

पंजाब की माताओं–बहनों से अपील – अब चुप न रहें, सोई हुई सरकार को जगाएं

मनदीप कौर

चंडीगढ़, – पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष शर्मा ने आज आम आदमी पार्टी सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा कि भाजपा और आप की राजनीति में सबसे बड़ा फर्क यही है कि भाजपा जनता से किया हर वादा निभाती है, जबकि आम आदमी पार्टी जनता को केवल झूठे सपनों और फरेब के जाल में उलझाती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने सिर्फ़ एक साल के भीतर महिलाओं को ?2100 प्रति माह देने का अपना वादा पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह राशि सीधे महिलाओं के खातों में डालकर दिखा दिया कि

भाजपा सरकार केवल वादों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जनता के जीवन में बदलाव लाने वाले ठोस कदम उठाती है। डॉ. शर्मा ने पंजाब सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि मान सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने का बड़ा वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के साढ़े तीन साल बाद भी महिलाओं के खाते खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह साफ़ साबित करता है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति सिर्फ़ घोषणाओं, भाषणों और प्रचार की राजनीति है, काम की नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 卐मान सरकार के मुख्यमंत्री मंच से बड़ी–बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं को अब तक एक रुपया भी नहीं मिला। वादाखि़लाफी और झूठ बोलना अगर कोई सीखना चाहे, तो आम आदमी पार्टी से सीखे।डॉ. शर्मा ने जोर देकर कहा कि भाजपा चाहे केंद्र में हो या राज्यों में, जनता से किया गया हर वादा पूरा करती है। हरियाणा में महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाना इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। इसके विपरीत पंजाब की मान सरकार ने जनता से विश्वासघात किया है और महिलाओं के साथ खुली धोखाधड़ी की है। उन्होंने पंजाब की माताओं और बहनों से सीधी अपील करते हुए कहा,卐अब और चुप मत रहिए। अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। मान सरकार को उसके झूठ और वादाखि़लाफी के लिए जवाबदेह ठहराइए। अगर आप अपनी हक़ की लड़ाई नहीं लड़ेंगी, तो यह सरकार यूं ही वादे करती रहेगी और माताओं–बहनों को ठगती रहेगी

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हॉकी की प्राचीन शान को पुनः बहाल करने का संकल्प लिया

खेलों, विशेषकर हॉकी के प्रति लगाव को याद किया, कहा, पंजाब के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का नाम फिर से रोशन किया

मनदीप कौर

जालंधर, – पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज प्रदेश में हॉकी की प्राचीन शान को पुनः बहाल करने का संकल्प लिया। आज यहां पंजाब हॉकी लीग 2025 के फाइनल मैच के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व और संतुष्टि का विषय है कि पहली जूनियर हॉकी लीग पंजाब हॉकी और राउंड ग्लास अकादमी द्वारा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यह हॉकी के क्षेत्र में अब तक की सबसे अधिक इनामी राशि वाली लीग है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह लीग मोहाली से शुरू हुई थी और इसके फाइनल मुकाबले जालंधर में खेले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए कई लीग मैच आयोजित होते हैं, वहीं यह देश की पहली जूनियर लीग है। उन्होंने कहा कि यह एक यादगार अवसर है क्योंकि सुरजीत हॉकी स्टेडियम में पंजाब के महान हॉकी खिलाड़ी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, एकत्र हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदर्शनी मैच में फ्लेजेंड इलेवनफ का मुकाबला फ्स्टार इलेवनफ से हुआ। उन्होंने कहा कि लेजेंड इलेवन की अगुवाई भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान ओलंपियन गगन अजीत सिंह ने की, जो वर्तमान में मालेरकोटला के एसएसपी हैं, जबकि स्टार इलेवन की अगुवाई मौजूदा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरजीत हॉकी स्टेडियम ने

भारतीय हॉकी के इतिहास में बेहद अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने इसे खुशी का क्षण बताया क्योंकि 1975 का हॉकी विश्वकप जीतने वाले खिलाड़ी और 2001 में जूनियर विश्वकप जीतने वाले खिलाड़ी इस स्टेडियम में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने हॉकी की तीन पीढ़ियों को एक साथ जोड़ा है और पंजाब का देश के लिए खेलों में सबसे बड़ा योगदान हॉकी में रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंजाब जूनियर हॉकी लीग का फाइनल है और इसकी खास बात यह रही कि इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से टीमें खेलने आईं। उन्होंने कहा कि इस जूनियर हॉकी लीग में अब तक की सबसे अधिक इनामी राशि रखी गई थी। यह लीग मोहाली से शुरू हुई और अब इसका फाइनल दोआबे की धरती जालंधर में खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में एशिया कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में नौ खिलाड़ी पंजाब से थे। उन्होंने कहा कि पिछले दो ओलंपिक खेलों में, जहाँ भारत ने पदक जीते, हर बार पंजाब के नौ खिलाड़ी टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने कहा कि जालंधर को फ्स्पोर्ट्स कैपिटलफ कहा जाता है और बरलटन पार्क, सुरजीत हॉकी स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉलेज दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पेरिस ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम में जालंधर के चार खिलाड़ी – मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, हार्दिक सिंह और सुखजीत सिंह शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जालंधर में बने फुटबॉल, रग्बी बॉल और अन्य खेल उपकरण विश्वकप और कॉमनवेल्थ खेलों में इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज़ जालंधर में बने क्रिकेट बैट से खेलते हैं और पंजाब में खेलों की जड़ें जालंधर से जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जालंधर में जन्मे क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया और उनके योगदान के कारण उन्हें राज्यसभा सदस्य नामित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार जालंधर को खेलों के केंद्र के रूप में और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने सात खिलाड़ियों को डीएसपी और चार खिलाड़ियों को पीसीएस अधिकारी नियुक्त किया है, जिनमें नौ हॉकी खिलाड़ी, एक क्रिकेटर और एक एथलीट शामिल हैं। उन्होंने इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की और कहा कि वे स्वयं बड़े खेल प्रेमी हैं, इसलिए खेल विभाग का प्रभार अपने पास रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के गाँवों में 3000 से अधिक खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खेल पहले ही पंजाब में युवाओं को नशे की लत से दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि जालंधर के बरलटन पार्क को पहले ही खेल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और अब अमृतसर में भी विश्वस्तरीय खेल केंद्र विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, हॉकी पंजाब के प्रधान और हॉकी इंडिया के उपप्रधान नितिन कोहली, राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल और अन्य ने फ्चढ़दी कला मिशनफ में योगदान स्वरूप मुख्यमंत्री को 50 लाख रुपये का चेक भेंट किया।

केंद्रीय संचार ब्यूरो, जालंधर ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत श्रमदान का आयोजन किया

छात्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान में सक्रियता से भाग लें–प्रिंसिपल संजय शर्मा

एस. के. सक्सैना

जालंधर– केंद्रीय संचार ब्यूरो, जालंधर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देवी सहाय एस.डी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जालंधर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत श्रमदान का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य स्वच्छता, स्वस्थ पर्यावरण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना था। यह कार्यक्रम केंद्रीय संचार ब्यूरो, जालंधर द्वारा सहायक निदेशक राजेश बाली के नेतृत्व में आयोजित किया गया था और विभाग के क्षेत्रीय प्रचार सहायक गुरकमल सिंह और प्रमोद ठाकरान ने इस अभियान में भाग लिया और कार्यक्रम की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया। अभियान की शुरुआत में, सभी प्रतिभागियों को स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई गई, जिसमें उन्होंने स्वच्छता और मिशन के उद्देश्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस स्वच्छता अभियान में, स्कूल के आसपास के क्षेत्र की सफाई की गई, जहाँ छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, कचरा एकत्र किया और उसका उचित निपटान सुनिश्चित किया। विद्यार्थियों को स्वच्छता के महत्व, स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों और स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने में व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए, स्कूल के प्रिंसिपल संजय शर्मा ने बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने और अपने आस–पास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया और सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन अभियानों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को खुले में शौच को समाप्त करने, स्वच्छता के बुनियादी ढाँचे में सुधार, स्वच्छता को बढ़ावा देने और जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों/एनसीसी स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वच्छता अभियान में सक्रिय योगदान दिया। इस अवसर पर स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक वीवीएन सोफत, एनसीसी अधिकारी चंदन चड्ढा, जसपाल सिंह और पीटी शिक्षक सरताज सिंह ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया।

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए डिप्टी कमिश्नर को 25 लाख रुपये का चैक सौंपा

बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा यह योगदान – डा. हिमांशु अग्रवाल

रमन कुमार

जालंधर, 25 सितंबर–हाल ही में आई बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए जालंधर के वरिष्ठ नागरिक इंदरजीत सिंह गुलाटी ने आगे आकर डिप्टी कमिश्नर डा.हिमांशु अग्रवाल को मुख्यमंत्री रंगला पंजाब फंड के लिए 25 लाख रुपये का चैक सौंपा है। डिप्टी कमिश्नर ने श्री गुलाटी के इस सहानुभूतिपूर्ण प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह योगदान बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में इस तरह के योगदान न

केवल मुश्किल समय में लोगों को सहारा देते है, बल्कि समाज में दया, सहानुभूति और सहयोग की नई मिसालें भी स्थापित करते है। उन्होंने कहा कि इस राशि से बाढ़ पीड़ितों के लिए चल रहे राहत कार्यों को और मजबूती मिलेगी। डा.अग्रवाल ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा दिया गया योगदान बेहद कीमती होता है और मुश्किल समय में पीड़ितों की मदद करना हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि श्री गुलाटी द्वारा दिखाई गई संवेदनशीलता से अन्य दानवीरों और सामाजिक संगठनों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने अन्य समाजसेवियों से भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की।

पटाखा व्यापारियों ने डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर,निगम कमिश्नर, और मेयर वनीत धीर, का जताया आभार

सरदार बेअंत सिंह पार्क में कारोबार करने के लिए जगह देने पर सभी कारोबारीयो ने प्रशासनिक अधिकारियों का किया धन्यवाद

पंकज

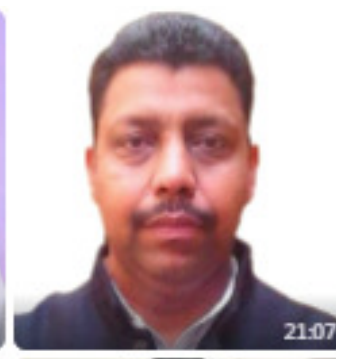

जालंधर–जालंधर शहर में पटाखा व्यापारियों ने डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर, निगम कमिश्नर संदीप ऋषि और मेयर वनीत धीर का सभी पटाखा व्यापारियों को सरदार बेअंत सिंह पार्क में पटाखा बेचने के लिए जगह देने पर उनका आभार व्यक्त किया हैथ व्यापारियों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें सुखद माहौल में कारोबार करने के लिए उपयुक्त जगह प्रदान की है, जिसके लिए वे उनके आभारी हैं महावीर बजरंगबली फायरवर्क्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि महाजन, राजेश जैन,जालंधर फायरवर्क्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास भंडारी, जालंधर

होलेसले फायरवर्क्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव बाहरी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की इस पहल से उन्हें अपने व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाने में मदद मिलेगी और ग्राहकों को भी सुविधा होगीथ उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का यह कदम व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जो सराहनीय है इस अवसर पर पटाखा व्यापारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी इस पहल से शहर में दिवाली के त्योहार को लेकर उत्साह और बढ़ेगाथ उन्होंने कहा कि वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे और शहर में दिवाली के त्योहार को सफल बनाने में अपना योगदान देंगेथ

मोदी बेमिसाल नेता–कार्यकुशल कर्मयोगी

लेखक
श्री हरदीप सिंह पुरी
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की करिश्माई उपस्थिति और संगठनात्मक नेतृत्व की भरपूर प्रशंसा की गई है, लेकिन जिस बात को कम ही लोग जानते और समझते हैं, वह यह है कि उनकी कठोर प`श`ावर

प्रतिबद्धता ही उनके काम की विशेषता है। गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पिछले ढाई दशकों में उनकी कार्यशैली में निरंतर पेशेवर नैतिकता विकसित हुई है।

जो बात उन्हें औरों से अलग बनाती है, वह प्रदर्शन की प्रतिभा नहीं, बल्कि ऐसा अनुशासन है, जो विजन को टिकाऊ प्रणालियों में तब?दील करता है। भारतीय मुहावरे में कहा जाए, तो वह कर्मयोगी हैं- कर्तव्य पर आधारित ऐसा कर्म, जिसका आकलन जमीनी स्?तर पर आए बदलाव से होता है।

यही नैतिकता इस वर्ष लाल किले से उनके स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का आधार रही। उनके इस भाषण में उपलब्धियों का लेखा–जोखा कम और मिल–जुलकर कार्य करने का चार्टर ज़्यादा प्रस्तुत किया गया- नागरिकों, वैज्ञानिकों, स्टार्ट–अप्स और राज्यों को विकसित भारत के सह–लेखक के रूप में आमंत्रित किया गया। गहन प्रौद्योगिकी, स्वच्छ विकास और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वाकांक्षाओं को कोरे शब दों में नहीं, बल्कि व्यावहारिक कार्यक्रमों के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन कार्यक्रमों को जनभागीदारी, यानी बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने वाले राज्य और उद्यमी लोगों के बीच की साझेदारी को एक पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया गया।

हाल ही में किया गया जीएसटी ढाँचे का सरलीकरण इसी पद्धति को दर्शाता है। स्लैब को कम करके और अवरोधों को दूर करके, परिषद ने छोटी फर्मों के लिए अनुपालन लागत कम की है और इसका लाभ सीधे घर–घर तक पहुँचाने की गति बढ़ाई है। प्रधानमंत्री का ध्यान संक्षिप् त राजस्व वक्रों पर नहीं, बल्कि इस बात पर था कि क्या आम नागरिक या छोटा व्यापारी इस बदलाव को जल्दी महसूस कर पाएगा या नहीं। यह स् वाभाविक प्रवृत्ति उस सहकारी संघवाद को प्रति ध् वनित करती है, जिसने जीएसटी परिषद का मार्गदर्शन किया है- राज्य और केंद्र गहन विचार–विमर्श करते हैं, लेकिन सभी एक ऐसी प्रणाली के भीतर काम करते हैं जो स्थिर रहने के बजाय परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाती है। नीति को एक जीवंत साधन माना जाता है, जो कागज़ पर समरूपता के लिए संरक्षित एक स्मारक के रूप में न रहकर अर्थव्यवस्था की लय के अनुरूप ढाली गई है।

यही वह व्यावसायिक दृ ष्टिकोण है, जो अमेरिका से वापसी की 15 घंटे की लंबी उड़ान के बाद देर रात बिना किसी सूचना के निर्माणाधीन नए संसद भवन के गेट पर पहुंचने की बात को समझाता है।

हाल ही में मैंने प्रधानमंत्री से पंद्रह मिनट का समय माँगा था। इस

दौरान हुई चर्चा के दौरान मैं उनकी व्यापक समझ और बहुआयामी दृष्टिकोण – एक ही फ्रेम में समाहित बारीक से बारीक विवरण और व्यापक संपर्क देखकर आश चर्य चकित रह गया। यह बैठक पैंतालीस मिनट चली। सहकर्मियों ने बाद में मुझे बताया कि उन्होंने इसकी तैयारी में दो घंटे से ज़्यादा समय लगाया, नोट्स, आँकड़े और प्रतिवादों का अध ययन किया। तैयारी का यह स्तर कोई अपवाद नहीं है; यह कार्य का वह मानदंड है, जिसे उन् होंने स् वयं के लिए निर्धारित किया है और जिसकी वह व्यवस्था से भी अपेक्षा रखते हैं। निरंतर तैयारी की यही आदत सुनिश्चित करती है कि निर्णय ठोस और भविष्य के लिए उपयुक्त हों।

भारत की हाल की प्रगति का अधिकांश आधार उन व् यवस् थाओं और प्रणालियों पर टिका है, जिन्हें हमारे नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिजिटल पहचान, सार्वभौमिक बैंक खाते और रीयल–टाइम भुगतान की त्रिमूर्ति ने समावेशन को बुनियादी ढाँचे में बदल दिया है। लाभ सीधे सत्यापित नागरिकों तक पहुँचते हैं; उचित व् यवस् था के कारण गड़बड़ियाँ कम होती हैं; छोटे व्यवसायों को अनुमानित नकदी प्रवाह मिलता है; और नीतियाँ धारणाओं की बजाय आँकड़ों पर आधारित होती हैं। इस प्रकार अंत्योदय – अंतिम नागरिक का उत्थान – यह एक नारा भर नहीं, बल्कि मानक बन जाता है – और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचने वाली प्रत्येक योजना, कार्यक्रम और फ़ाइल की असली कसौटी बन जाता है।

असम के नुमालीगढ़ में भारत के पहले बांस–आधारित 2जी इथेनॉल संयंत्र के शुभारंभ के दौरान मुझे एक बार फिर इसका साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। इंजीनियरों, किसानों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ खड़े होकर, प्रधानमंत्री ने सीधे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रश्न पूछे – किसानों को भुगतान उसी दिन कैसे प्राप्त होगा; क्या आनुवंशिक इंजीनियरिंग से ऐसा बाँस तैयार किया जा सकता है, जो तेज़ी से बढ़ता है और गांठों के बीच बाँस के तने की लंबाई बढ़ाता है; क्या महत्वपूर्ण एंजाइमों का स्वदेशीकरण किया जा सकता है; क्या बाँस के हर घटक–तना, पत्ती, अवशेष का इथेनॉल से लेकर फुरफुरल और ग्रीन एसिटिक एसिड तक– आर्थिक उपयोग किया जा रहा है, चर्चा केवल तकनीक तक ही सीमित नहीं थी। यह लॉजिस्टिक स, आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन और वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट तक व याप् त रही। अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में भाग लेने वाले व्यक्ति के रूप में, मैंने इस पद्धति को तुरंत पहचान लिया- संक्षिप्त विवरण की स्पष्टता, विवरण में सटीकता और इस बात पर ज़ोर कि कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति पहला लाभार्थी होना चाहिए।

यही स्पष्टता भारत की आर्थिक नीति को भी जीवंत करती है। ऊर्जा के क्षेत्र में, विविध आपूर्तिकर्ता समूह और संयमित ठोस खरीदारी ने उतार–चढ़ाव भरे समय में हमारे हितों को सुरक्षित रखा है। विदेश में एक से ज़्यादा मौकों पर, मेरे पास बेहद सरल निर्देश था- आपूर्ति सुनिश्चित करना, सामर्थ्य बनाए रखना और भारतीय उपभोक्ताओं को केंद्र में रखना। उस स्पष्टता का सम्मान किया गया और परिणामस्वरूप बातचीत और भी सुचारू रूप से आगे बढ़ी।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी किसी तरह के दिखावे से परहेज किया गया है। दृढ़ संकल्प और संयम के साथ संचालित अभियानों–लक्ष्य स्पष्ट, सैन्य बलों को संचालन की स्वतंत्रता, निर्दोषों की सुरक्षा–में शोरगुल के बजाय भरोसे को तरजीह दी गई। नैतिक सिद्धांत एक ही है- कड़ी मेहनत करो, परिणाम स् वयं सामने आएंगे।

इन विकल्पों के पीछे एक विशिष्ट कार्यशैली छिपी है। चर्चाएँ सभ्य, लेकिन कठोर होती हैं; परस्पर विरोधी विचारों का स्वागत है, लेकिन भ्रम की कोई जगह नहीं है। सभी की बात सुनने के बाद, वह एक मोटे दस्तावेज़ को ज़रूरी विकल्पों तक सीमित कर देते हैं, ज़िम्मेदारी सौंपते हैं और सफलता तय करने के मापदंड बताते हैं। सबसे ज़ोरदार तर्क नहीं, बल्कि सबसे अच्छे तर्क की जीत होती है; तैयारी का सम् मान किया जाता है; निरंतर फॉलोअप किया जाता है। सहकर्मियों के लिए, यह तैयारी एक सीख होती है; व्यवस्था के लिए, यह एक ऐसी संस्कृति है, जहाँ परिणाम की गुणवत ता का अनुमान नहीं लगाया जाता, बल्कि उसका आकलन किया जाता है।

यह कोई संयोग नहीं है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन दिव्य शिल्पी– विश्वकर्मा की जयंती वाले दिन ही पड़ता है। यह समानता शाब्दिक नहीं, बल्कि शिक्षाप्रद है- सार्वजनिक जीवन में, सबसे स्थायी स्मारक संस्थाएँ, मंच और मानक होते हैं। नागरिक के लिए, कार्य निष पादन एक ऐसा लाभ है, जो समय पर मिलता है और एक ऐसी कीमत, जो उचित रहती है; उद्यम के लिए, यह नीतिगत स्पष्टता और विस्तार का एक विश्वसनीय मार्ग है; राज्य के लिए, यह ऐसी व्यवस्थाएँ हैं, जो दबाव में भी टिकी रहती हैं और उपयोग के साथ बेहतर होती जाती हैं। नरेन् द्र मोदी को इसी मापदंड से देखा जाना चाहिए; एक ऐसे कर्मयोगी के रूप में जिनका कार्य निष पादन दिखावा नहीं, बल्कि एक ऐसी सेवा है, जो भारतीय इतिहास के अगले अध्याय को आकार दे रही है।

लेखक केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं।